PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 195 ● भिलाई, सोमवार 09 फरवरी 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

सांसद पप्पू यादव 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार

पटना। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना पुलिस ने उनके मंदिरी स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट द्वारा जारी वारंट के आधार पर की गई है। गिरफ्तारी के दौरान करीब तीन घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चला, जिसमें पप्पू यादव के बेहोश होने और समर्थकों के भड़कने की खबरें भी सामने आईं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने डाला घेरा शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में 5 डीएसपी, 6 थानेदार और लगभग 100 पुलिसकर्मियों की टीम पप्पू यादव के आवास पर पहुंची। अचानक हुई इस छापेमारी से आवास पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब उन्हें साथ चलने को कहा, तो पप्पू यादव और उनके करीबियों की पुलिस अधिकारियों से तीखी नोक-झोंक हुई। सिविल ड्रेस में पुलिस रात के अंधेरे में मुझे गिरफ्तार करने आई है। मेरे पास कोई वारंट नहीं दिखाया गया। यह मुझे मारने की साजिश हो सकती है। मैं रात में कहीं नहीं जाऊंगा, पुलिस चाहे तो मुझे हाउस अरेस्ट कर ले।

रोहित शेट्टी फायरिंग केस : 20 जनवरी को स्कूटी लेकर मुंबई आए थे आरोपी

मुंबई । मुंबई में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया था और अब मामले की गुत्थी धीरे-धीरे खुलती नजर आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में घटना की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि इसमें अवैध हथियारों की सप्लाई, बड़े पैमाने पर फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की संभावना है। पुलिस के अनुसार, 20 जनवरी को आरोपी सिद्धार्थ और समर्थ दोपहिया वाहन लेकर पुणे से मुंबई पहुंचे थे। उनका उद्देश्य उस शूटर तक स्कूटर पहुंचाना था, जिसे विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास खड़ा किया गया था। शूटर, जो बिहार का रहने वाला बताया गया है, अपने चार-पांच साथियों के साथ मुंबई में रुका था और कथित तौर पर फायरिंग से पहले रोहित शेट्टी के घर की तीन-चार बार रेकी कर चुका था। जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं।

एनसीआर में तेज हवाओं का असर, ठंड बढ़ी, वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इन दिनों तेज सतही हवाओं के चलते मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय लोगों को गलन भरी ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तेज धूप और हवाओं की वजह से तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार 7 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों का साथ जरूरी

मलेशिया/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और मलेशिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। पीएम मोदी ने मलेशिया में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात को भावनात्मक और विशेष अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों में मलेशियाई नेतृत्व के प्रति सम्मान और अपनापन साफ दिखाई देता है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की अहमियत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दोनों देशों की शांति और समृद्धि एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और मलेशिया को मौजूदा वैश्विक हालात में अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत और मलेशिया के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी दोनों देश अहम साझेदार बनकर उभरे हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर भी सकारात्मक प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ASEAN की अध्यक्षता के लिए मलेशिया को बधाई दी और उम्मीद जताई कि मलेशिया के नेतृत्व में भारत-ASEAN संबंध और

अधिक मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-मलेशिया संबंधों की असली मजबूती लोगों के बीच के रिश्तों में दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि मलेशिया में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी मलेशिया की तीसरी यात्रा है और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से उनकी चौथी मुलाकात, जो दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ती निकटता को दर्शाती है। उन्होंने बीते वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में आई गति और गहराई के लिए मलेशियाई नेतृत्व का आभार जताया। पीएम मोदी ने मलेशिया में मिले गर्मजोशी भरे और पारंपरिक स्वागत के लिए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और उनकी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस सुंदर तरीके से मलेशियाई संस्कृति और जीवनशैली को प्रस्तुत किया गया, वह हमेशा यादगार रहेगा। वहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिन्हें दोनों देशों की टीमें आगे बढ़ाएंगी। अनवर इब्राहिम ने सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताते हुए इस यात्रा को अपने लिए व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण बताया।

आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की जरूरत

पीएम मोदी ने कहा, कल मुझे आपके डायस्पोरा से मिलने का अवसर मिला, और यह एक खास अनुभव था। मैंने देखा कि आपके लिए डायस्पोरा में कितना सम्मान और लगाव है, जो मुझे गर्व महसूस कराता है। आतंकवाद के खिलाफहमारी लड़ाई में दोस्त देशों का समर्थन बहुत जरूरी है। हमारा पक्का विश्वास है कि भारत और मलेशिया की खुशहाली एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में, भारत और मलेशिया के लिए अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि उनका उद्देश्य भारत और मलेशिया के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है और हर संभव क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।

चुनाव आयोग बना भाजपा का सहयोगी दल

उसके ऑफिस पर बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक परंपरा खतरे में है। लखनऊ में आज अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था के बजाय भाजपा के सहयोगी दल की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की काली करतूतों के कारण समाजवादी पार्टी को मजबूर होकर काला कोट पहनना पड़ा और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कार्यालय पर भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि चुनाव नियमों की धारा 31 और 32 का खुला उल्लंघन किया जा रहा।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।

एसआईआर पर बहुत बड़ा फैसला

अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा मान्य-आयोग....

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र को पहचान और पात्रता के लिए एक वैध दस्तावेज माना जाएगा। यह कदम उन मतदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो निवास प्रमाण को लेकर संशय में थे। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए एक पत्र में, भारतीय निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि 27 अक्टूबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में पीआरसी को पहले ही शामिल किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य में अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र मुख्य रूप से 2 नवंबर 1999 को जारी सरकारी आदेशों के आधार पर बनाए जाते हैं। वैसे, एसआईआर में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आयोग ने सख्त हिदायत भी दी है।

शिवराज सिंह चौहान ने गिनाए सुरक्षा चक्र

अमेरिकी उत्पादों के लिए बंद रहेंगे भारत के दरवाजे-चौहान

नई दिल्ली/ एजेंसी

एक तरफ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के लिए स्वर्णिम अवसर बता रहे हैं, वहीं किसान संगठनों ने 12 फरवरी को इस डील के विरोध में 'भारत बंद' और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। समझिए कृषि मंत्री की प्रेस कांफ्रेंस में क्या-क्या खास रहा। भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने देश की राजनीति और कृषि क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। जहां केंद्र सरकार इसे भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार खोलने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और

किसान संगठनों ने इसे 'किसान विरोधी' करार दिया है। इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभालते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय किसानों का हित 'सर्वोपरि' है और उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया गया है।शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों को समझौते से बाहर रखा गया है। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज और दलहन (मूंग, काबुली चना) जैसे प्रमुख अनाजों पर टैरिफ में कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा, डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए अमेरिका से लिक्विड दूध, घी, मक्खन, पनीर, योगर्ट और क्रीम जैसे उत्पादों की एंट्री पर रोक बरकरार रखी गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, भारत के मसाला बाजार को भी कवच प्रदान किया गया है। काली मिर्च, हल्दी, अदरक, जीरा, हींग और धनिया सहित लगभग सभी प्रमुख मसालों को सुरक्षित सूची में रखा गया है।

ट्रेड डील पर ऐलान के बाद भारत के लिए आई अच्छी खबर, रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने हटाया 25 प्रतिशत टैरिफ

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं और मॉस्को से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने का आश्वासन दिया है। जारी एक कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी और सिफारिशें मिली हैं, जिनके अनुसार भारत ने कार्यकारी आदेश 14066 में बताई गई राष्ट्रीय आपात स्थिति से निपटने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने और अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने का वादा किया है।

एसआईटी का बड़ा धमाका!

गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

असम/ एजेंसी

असम में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के कथित पाकिस्तानी संपर्कों को लेकर कई अहम और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एसआईटी ने इस मामले में पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख को मुख्य कड़ी (हैंडलर) के रूप में चिह्नित किया है। अली तौकीर शेख पाकिस्तान के योजना आयोग का सलाहकार बताया जा रहा है। एसआईटी के अनुसार, अली तौकीर शेख एलिजाबेथ गोगोई का करीबी सहयोगी है और

उसने ही 'लीड पाकिस्तान' नाम की एनजीओ की स्थापना की थी। यही वह संगठन है, जहां कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई ने काम किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि शेख सोशल मीडिया पर भारत के आंतरिक मामलों, संसद और राजनीतिक मुद्दों पर लगातार टिप्पणी करता रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि अली तौकीर शेख की ऑनलाइन गतिविधियां भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के इरादे को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती हैं। शेख बार-बार भारत की घरेलू राजनीति और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर राय देता रहा है।एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अली तौकीर शेख ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों और थिंक टैंक नेटवर्क के जरिए भारत में अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाया। जांच के मुताबिक, शेख और एलिजाबेथ गोगोई भारत-पाकिस्तान से जुड़े सीडीकेएन क्लाइमेट नेटवर्क का भी हिस्सा रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री की समीक्षा बैठक में बस्तर पर खास फोकस

नक्सलवाद से विकास की ओर छत्तीसगढ-केंद्रीय गृहमंत्री शाह

रायपुर/ संवाददाता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में वामपंथी उग्रवा दछत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति और बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सुरक्षा, प्रशासन और विकास से जुड़े कई अहम पहलुओं पर मंथन हुआ। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का केंद्र माना जाता था, वह आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के तहत विकास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा अब खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने, नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने और प्रभावित इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र को आदिवासी संभाग के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि विकास और सुरक्षा की रणनीति साथ-साथ आगे बढ़े, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित हो सके। इस उच्चस्तरीय बैठक में

केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल,आईओबीपी के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सहित छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बस्तर पंडुम समापन समारोह में 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर। बस्तर की जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्पित तीन दिवसीय बस्तर पण्डुम का समापन समारोह 9 फरवरी को एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह विशेष तौर पर शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे। 'प्रकृति और परंपरा का उत्सव' के ध्येय वाक्य के साथ मनाया जा रहा यह आयोजन बस्तर की माटी की खुशबू और यहां की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है। इस गरिमामयी समापन समारोह का आयोजन 9 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से लालबाग मैदान जगदलपुर में निर्धारित है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, कौशल विकास मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े शामिल होंगे। बस्तर पण्डुम में सांसद द्वय श्री महेश कश्यप और श्री भोजराज नाग, विधायक श्री किरण सिंहदेव, सुश्री लता उसेंडी, श्री विनायक गोयल, श्री नीलकंठ टेकाम, श्री विक्रम उसेंडी, श्री आशाराम नेताम, श्री चैतराम अटामी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री लखेश्वर बघेल, श्री विक्रम मंडावी, महापौर श्री संजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम से पहले सियासी संग्राम, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा पर भड़का विवाद

अधिकारी राज हावी होने का आरोप, नपाध्यक्ष ने महिला बाल विकास अधिकारी पर साधा निशाना, माफी नहीं तो प्रदेश स्तर तक ले जाने की चेतावनी

बालोद। जिला मुख्यालय में आगामी 10 फरवरी को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। शहर के एक निजी राइस मिल में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब आयोजन में जनप्रतिनिधियों की कथित उपेक्षा ने मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव में बदल दिया है। दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम के लिए जारी किए गए आमंत्रण पत्र में नगर पालिका परिषद बालोद के सभापति और महिला बाल विकास समिति की सभापति गोमती रात्रे का नाम शामिल नहीं किए जाने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। इस मुद्दे को लेकर सभापति गोमती रात्रे सहित पार्षद गोकुल ठाकुर, प्रीतम साहू, पुष्पा साहू और श्यामा यादव ने कलेक्टर से मुलाकात कर विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आमंत्रण पत्र को संशोधित कर जनप्रतिनिधियों का नाम शामिल करने की मांग की है। गोमती रात्रे ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे मामले को प्रदेश स्तर तक ले जाएंगी।

डीपीओ नही करते कॉल रिसीव : प्रतिभा

वहीं इस पूरे विवाद में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी भी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार की मंशा की सराहना की, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की अनदेखी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। नपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी समीर पांडे से संपर्क करने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं किया और न ही वापस संपर्क किया। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताते हुए कहा कि विभाग को आदिवासी महिला जनप्रतिनिधि का नाम आमंत्रण पत्र में शामिल करने में आखिर क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि यदि उनके पीआईसी सदस्य और पार्षद का सम्मान नहीं किया जाता तो इसे वे व्यक्ति गत अपमान मानती हैं। प्रतिभा चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इस योजना या कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगी क्योंकि यह बेटियों के विवाह से जुड़ा संवेदनशील विषय है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग कि संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, अन्यथा इस मुद्दे को उच्च स्तर तक उठाया जाएगा।

मामला पकड़ा सियासी तूल

अब यह मामला प्रशासन और सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि वह विवाद को सुलझाने के लिए क्या रुख अपनाता है और क्या जनप्रतिनिधियों की नाराजगी दूर हो पाती है या यह मामला और ज्यादा सियासी तूल पकड़ता है। बहरहाल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम के बीच उभरा यह विवाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है।

ग्रीष्मकालीन धान की अवैध सिंचाई पर उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई, 13 नग मोटर पंप जब्त

बेमेतरा। ग्रीष्मकालीन धान की अवैध सिंचाई पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी एवं सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बीते दिवस विभागीय उड़नदस्ता टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्रीष्मकालीन धान की सिंचाई करते किसानों को पकड़ा गया। उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम ताकम से 07, पाथरपूंजी से 02, सिंवार से 01 तथा सलधा से 03 नग मोटर पंप जप्त किए। इस प्रकार कुल 13 नग पंप जप्त कर नियमानुसार जब्ती की कार्यवाही की गई। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित कृषकों द्वारा जल संरक्षण एवं शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रतिबंधित अवधि में ग्रीष्मकालीन धान की सिंचाई की जा रही थी, जिससे भू-जल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन द्वारा पूर्व में ही किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने एवं जल के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु निर्देशित किया गया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जल संरक्षण अधिनियम एवं संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही कृषकों से अपील की गई है कि वे शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जल का सदुपयोग करें तथा वैकल्पिक, कम पानी वाली फसलों की ओर अग्रसर हों। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध सिंचाई पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित उपकरणों की जब्ती की कार्यवाही और कड़ी की जाएगी।

बालोद जिला अध्यक्ष श्याम जायसवाल ने उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से की मुलाकात

दल्लीराजहरा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा बालोद जिला अध्यक्ष श्याम जायसवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से मुलाकात कर बालोद जिले के दल्लीराजहरा, डौंडी व चिखलाकसा के आस पास के गांव में जमीन चिह्नांकित कर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की मांग रखी है।श्याम जायसवाल ने इन क्षेत्रों के आस पास में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। श्याम जायसवाल ने कहा कि बालोद जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या नगर पालिका दल्लीराजहरा की है। साथ ही यहां बीएसपी सहित कई कंपनी खनन का कार्य कर रहे हैं। जिससे यहां सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से मजबूत है। दल्लीराजहरा में रेल नेटवर्क व अच्छी सड़क है, साथ ही डौंडी ब्लॉक में ग्राम नर्राटोला के में बीएसपी द्वारा निर्मित 40 एकड़ की हवाई पट्टी है। जिसे विमानन मंत्रालय को हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही हैं। भविष्य में विमान सेवा शुरू किए जाने पर वायुमार्ग कनेक्टिविटी भी हो जाएगी आस पास सैकड़ों गांव है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दल्लीराजहरा, चिखलाकसा, डौंडी के आस पास की जमीन चिह्नांकित कर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते हैं। तो निश्चित तौर पर यहां कई निजी उद्योग स्थापित होंगे जिससे हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। रोजगार के लिए उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने इस प्रस्ताव पर विचार करने और उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।

सप्तगिरि पार्क दल्लीराजहरा में होगा 10 फरवरी को फ्लावर शो

दल्लीराजहरा। बीएसपी नगर प्रशासक विभाग के अंतर्गत आने वाले सप्तगिरि पार्क में फ्लावर शो 2026 का आयोजन 10 फरवरी 2026 को हो रहा है। इस आयोजन के लिए नगर प्रशासक से संबंधित इलेक्ट्रिकल विभाग सिविल विभाग जलप्रदाय विभाग एवं सप्तगिरी पार्क विभाग के कर्मचारी पूरे जोर-शोर से लगे हुए हैं। नगर प्रशासक मंगेश सेलकर ने बताया कि बीएसपी के पूरे विभाग के द्वारा फ्लावर शो के तैयारी के लिए सहयोग किया जा रहा है द्य फ्लावर शो को बेहतर बनाने के लिए सभी कर्मचारी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। लोग फ्लावर शो की तैयारी में अपने घर के बगीचे को सजाने में लग गए हैं। विभिन्न प्रकार के देशी व विदेशी फूल लगाए हैं। कुछ पौधे बाहर से मंगाए हैं। स्थानीय बाजार से भी पौधे खरीद कर क्यारी और गमले में लगाए हैं। कोई माली के माध्यम से तो कोई खुद अपना गार्डन तैयार करते हैं। दिसंबर से ही पौधों में फूल खिलना शुरू हो जाता है। टाउनशिप के अधिकांश क्वार्टर में हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। नगर प्रशासन विभाग राजहरा के द्वारा फ्लावर शो-2026 के आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता रखी गई है जो इस प्रकार से है- जैसे फ्लावर डेकोरेशन वेजिटेबल फ्रुट बास्केट, कट फ्लावर, पॉटेड प्लांट, रंगोली प्रतियोगिता चार कैटेगरी में होगा जिसमें हाई स्कूल 9वीं से 12वीं तक मिडिल स्कूल आठवीं तक सामान्य एवं प्रोफेशनल है।

नियम व शर्तें

सभी वर्ग में प्रवेश के लिए एक आवास के लिए प्रतियोगी द्वारा एक ही फार्म भरा जायेगा। प्रतियोगी को टीक मार्क (?) लगाना होगा जिसमें वह भाग लेना चाहता है। सभी वर्गों के लिये (क्र. 6 से 24 तक) अंतिम तिथि 09-02-2026 समय दोपहर 1:00 बजे तक।. प्रतियोगी को सज्जा सामान स्वयं लाना होगा, प्रदर्शनी के लिये तथा साज सज्जा समय सुबह 10:00 बजे तक समाप्त कर लेना होगा। निर्णय 11:00 बजे से शुरू किया जायेगा, निर्णायक का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रतियोगी रात 8:00 बजे से अपने प्रदर्शित सामग्री को ले जा सकते हैं। उसके बाद नगर प्रशासन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पॉटेड प्लांट के लिए प्रतियोगियों को स्वंय ही लाने एवं ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्थापकगण यथा संभव सुरक्षा का प्रयत्न करेंगे परन्तु किसी प्रकार की हानि की दशा में व्यवस्थापक जिम्मेदार नहीं होंगे। सभी प्रवेश को विशेष नम्बर दिया जायेगा। इसके अलावा अन्य कोई पहचान मार्क/स्लोगन/नाम इत्यादि लिखने की मनाही है।

फ्लावर हेतु कांच की बोतल साथ में लावें

एक परिवार केवल 4 प्रविष्टि में भाग ले सकते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रविष्टि में एक से अधिक सदस्य के नाम स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सांस्कृतिक कार्यकम में भाग लेने हेतु केवल 09 फरवरी 2026 को प्रात: 9.00 बजे से 12:00 बजे तक सप्तगिरी उद्यान में संपर्क करें। आवेदन, निर्धारित तिथि तक ही जमा लिया जायेगा उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

कोलिहापुरी में 8 व 9 फरवरी को रामायण सम्मेलन आयोजित

डोंगरगांव नगर। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोलिहापुरी में रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जय श्रीराम मानस नवयुवक मंडल के बैनरतले एवं ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित रामायण सम्मेलन 8 से 9 फरवरी तक आयोजित है। उक्त सम्मेलन में राज्य की प्रमुख मानस मंडलियाँ सम्मिलित होंगी। आयोजन समिति के अनुसार शुभारंभ 8 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे होगा। इस मौके पर मुख्यअतिथि कोमल सिंह राजपूत भाजपा जिलाध्यक्ष राजनांदगांव होंगे। अध्यक्षता दिनेश गांधी पुर्व जिपंअध्यक्ष दिनेश गांधी, विशिष्ट अतिथि प्रशांत कोडापे, भूपेंद्र वर्मा, मदन लाल देवांगन एवं ताराचंद सिन्हा उपस्थित रहेंगे। पश्चात आमंत्रित मानस मंडलियो की सुमधुर व भावपूर्ण प्रस्तुति होगी। निर्णायकों के मतानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त मानस मंडली को सम्मानित किया जाएगा।

आयोजकों ने बताया कि समापन समारोह 9 फरवरी को रात्रि 9 बजे से आयोजित होगा। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि दलेश्वर साहू विधायक डोंगरगांव होंगे। अध्यक्षता भावेश सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि मंजू नरेंद्र वर्मा, चेतन वर्मा, मदन लाल देवांगन सहित समस्त समस्त ग्राम पंचायत के पंचगण सम्मिलित होंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनी गरीब परिवारों की बेटियों का संबल

10 फरवरी को 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह

कवर्धा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए उम्मीद और सम्मान का मजबूत आधार बनकर सामने आई है। हर माता-पिता का सपना होता है कि वे अपनी बेटी का विवाह गरिमा और सामाजिक सम्मान के साथ कर सकें, लेकिन आर्थिक सीमाएं कई बार इस सपने को कठिन बना देती हैं। ऐसे समय में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने जरूरतमंद परिवारों को राहत और भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल से इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को और अधिक संबल मिल रहा है। जिले में बीते दो वर्षों के दौरान अब तक 724 जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका है। इसी क्रम में 10 फरवरी को कबीरधाम जिले के सरदार वल्लभभाई पटेल मैदान में आयोजित होने वाले भव्य सामूहिक विवाह समारोह में लगभग 251 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर वर्चुअल रूप से जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि यह आयोजन पूर्ण गरिमा, अनुशासन और उत्सवपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। इस योजना के तहत वैवाहिक संस्कार विधिवत रूप से पूरे किए जाते हैं और जिला प्रशासन अभिभावक की भूमिका निभाते हुए भोजन, पंडाल, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उददेश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और बेटियों के सम्मानजनक भविष्य को सुनिश्चित करना है।

डीएवी एमपीएस में जागरूकता एवं परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन

बेमेतरा। जिले का एक मात्र डी.ए.वी.स्कूल जांता, बेमेतरा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सामाजिक जागरूकता एवं नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उददेश्य से आओ छू लें आसमान को, परीक्षा टिप्स, परीक्षा पे चर्चा एवं जागरूकता विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी बेमेतरा कौशल्या साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ पुलिस विभाग बेमेतरा से वर्षा चौबे प्रधान आरक्षक तथा नोडल अधिकारी बलदाऊ पटेल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि कौशल्या साहू डीएसपी ने अपने प्रेरणादायी उदबोधन में छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, अपनी योग्यता बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि बेटियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में सजग व सतर्क रहकर स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने बालको में भी यह समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि लड़का और लड़की समान हैं तथा समाज में बेटियों, महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन, कर्तव्यों के पालन, बड़ों का सम्मान करने और स्वयं प्रसन्न रहकर जीवन जीने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच अपनाने, समय-सारणी बनाकर अध्ययन करने तथा आत्म-अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई। परीक्षा मार्गदर्शन सत्र में विद्यार्थियों को बताया गया कि प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होनी चाहिए। आज का कार्य कल पर न छोड़ने, पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करने, लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय बताए गए। उन्होंने यह भी समझाया कि केवल आसान और आकर्षक रास्तों के पीछे भागने के बजाय कठिन मार्ग अपनाने से ही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है। डी एस पी एवं प्रधान आरक्षक दोनों ने जागरूकता सत्र के दौरान गुड टच और बेड टच, पॉक्सो अधिनियम, नशा अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित जानकारी दी गई तथा उनके दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में भाईचारे, एकजुटता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया तथा विद्यार्थियों को एक जागरूक, अनुशासित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। इसी अवसर पर विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शुभकामना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गईं। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य पी.एल. जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डीएसपी बेमेतरा कौशल्या साहू के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायी मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को जीवन की सही दिशा मिली है। साथ ही उन्होंने प्रधान आरक्षक बेमेतरा पुलिस विभाग आभार व्यक्त किया व नोडल अधिकारी शबलदाऊ पटेल सहित समस्त उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद किया, जिन्होंने विद्यार्थियों को जागरूकता, अनुशासन एवं सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आगे उन्होंने विद्यार्थियों की ओर से यह विश्वास दिलाया कि वे अतिथियों द्वारा बताए गए मार्गदर्शन, मूल्यों एवं आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तथा अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और विद्यालय भविष्य में भी ऐसे उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। उन्होंने मुख्य अतिथि, पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों की ओर से यह विश्वास दिलाया कि वे अतिथियों द्वारा बताए गए मार्गदर्शन एवं मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ।

भूमि जल संरक्षण को लेकर बेमेतरा में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला

केंद्रीय जल बोर्ड के विशेषज्ञों ने जल संचयन, पुनर्भरण एवं प्रबंधन पर दिया तकनीकी मार्गदर्शन

बेमेतरा। गिरते हुए भूमि जल स्तर के कारण बेमेतरा जिले को क्रिटिकल श्रेणी में चिह्नांकित किया गया है। इसके चलते जिले में न केवल सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि पेयजल संकट भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निरंतर जन-जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित एवं निर्माणाधीन जल संरक्षण संरचनाओं की उचित स्थल पहचान, तकनीकी गुणवत्ता एवं दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जल बोर्ड, उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर के क्षेत्रीय निदेशक एवं उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा जिला पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में भूमि जल भंडारण विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तरीय समस्त अधिकारी, विकासखंड स्तर से मनरेगा अधिकारी एवं कर्मचारी, तकनीकी अमला सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण के महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं व्यवहारिक उपायों के प्रति प्रशिक्षित करना था, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण, वर्षा जल संरक्षण, जल संरचनाओं की डिज़ाइन एवं निर्माण में तकनीकी बारीकियाँ, तथा स्थानीय भू-भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा यह भी बताया गया कि वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित संरचनाएँ किस प्रकार लंबे समय तक भू-जल स्तर को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण से होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों की जानकारी दी गई तथा जिले में जल संकट से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रदान संस्था, तथा जनपद पंचायतों से जनपद सीईओ, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, एवं चयनित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।यह कार्यशाला जिले में स्थायी जल प्रबंधन एवं भू-जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

संक्षिप्त समाचार

सीएसआर का पहला सीईओ अंकित आनंद को बनाने की कवायद

रायपुर। छग में स्टेट केमिपटल रीजन बनाए जा रहे है जिसमें रायपुर, भिलाई, दुर्ग में नागरिक सुविधाएं बनाने एवं अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसका सेटअप मंजूर किया जा रहा है। सीएसआर में अंकित आनंद को सीईओ बनाने के लिए इस समय कवायद चल रही है। उन्होंने सीएसआर के ड्राप और सेटअप तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। मिली जानकारी के अनुसार नईदिल्ली कीतर्ज पर रायपुर में भी सीएसआर बनाया जा रहा है। राजधानी विकास प्रक्षेत्र के नाम से इसकी स्थापना की जा रही है ताकि औद्योगिक नगरी भिलाई दुर्ग तथा रायपुर का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसे पर्यावरण विभाग के तहत रखा गया है इसका सेटअप तैयार किया जा रहा है। इसके सीईओ का लेबल सेकेटरी स्तर का होगा। इस समय इस बात की चर्चा है सेकेटरी अंकित आनंद को सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाए। छग में इस समय इस सीएसआर को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। ज्ञात रहे राजधानी रायपुर का बेतरतीब ढंग से विकास हो रहा है। इसे रोकने के लिए तथा कालोनाइजर पर शिकंजा कसने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सीएसआर का कार्यक्षेत्र बड़ा होगा। रायपुर में मुख्यालय के अलावा दुर्ग भिलाई में इसका कार्यालय खोला जा सकता है।

अंतिम वित्तीय माह शासकीय चैक एवं भुगतान पर नियंत्रण के लिए आहरण पर रोक लगाने के निर्देश

रायपुर। अंतिम वित्तीय माह मार्च को देखते हुए अब वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन का डंडा घुमाया जा रहा है जिसके तहत अब सिंचाई रोककर तथा अन्य विभागों में चैक की भुगतान तथा अन्य खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के आदेश नियमानुसार जारी किये जा रहे है। इधर २५ -२६ के लिए आबंटित बजट राशि का खर्च करने के लिए धड़ल्ले से विभिन्न विभागों में कार्य किये जा रहे है। मिली जानकारी के अनुसार लोक निर्माण सिंचाई जल संसाधन तथा पंचायत एवं पीएचई में विभिन्न ठेकेदारों तथा बड़े काम कराये जाते हैं। वित्त विभाग ने परंपरानुसार अलग अलग महीनों में काम कराने का दिशा निर्देश दिया है। छग में वित्त माह मार्च से लेकर मार्च तक चलता है। वित्तीय अनुशासन रोकने के लिए चैक नगद के आहरण पर रोक लगाई जाती है। विभागीय ठेके दार अपने अपने काम के भुगतान के लिए बिल बनाते है। जिसका भुगतान 31 मार्च के पूर्व कराने का प्रयास किया जाता है लेकिन कतिपय तकनीकी कारणों से यहभुगतान नहीं हो पाता है आदिम जाति स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों में खरीदी बिक्री धड़ल्ले से जारी है जिसका भुगतान करने के लिए अब ठेकेदार विभागीय अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन वित्तीय अनुशासन के कारण भुगतान लटका हुआ है। कोषालय आयुक्त के अनुसार अभी यह निर्देश जारी किया जा रहा है जिसके तहत फरवरी के महीने तक सभी को अपना अपना भुगतान करना होगा। तथा चैक से भुगतान के आहरण पर रोक लगा दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सचिव वित्त विभाग से अनुमोदन लेकर आहरण किया जा सकता है जिला कोषालय में इस समय भुगतान के लिए कई बिल लंबित है। एक अनुमान के अनुसार राज्य में करोड़ो रुपये का भुगतान होने की संभावना है।

जेल प्रहरी के बर्खास्तगी आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

रायपुर। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर जेल प्रहरी को बर्खास्त किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया है। उक्त निर्देश जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को बिना ठोस साक्ष्य के दंडित किया जाता है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। बता दें कि जेल प्रहरी लखनलाल जायसवाल को 2 अगस्त 2024 को एक कैदी को चिकित्सा जांच के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अस्पताल में जांच के बाद वह शाम करीब 4:50 बजे कैदी के साथ जेल लौट आए। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए, जिनके आधार पर विभाग ने उन पर आरोप तय किए और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जेल प्रहरी पर आरोप था कि अस्पताल ले जाने के दौरान याचिकाकर्ता कैदी के परिजनों के साथ रायपुर के फाफ्डीह इलाके में एक रेस्तरां में अनाधिकृत रूप से घूमते दिखाई दिए वहीं कैदी को सुबह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बिना उचित कारण के देर शाम जेल वापस आ गये, जिससे कैदी के फरार होने का खतरा बन सकता था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने दलील दी कि आरोप अस्पष्ट हैं और उनमें समय, स्थान व अन्य आवश्यक विवरणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने कुछ परीक्षण सुझाए थे, जिनकी रिपोर्ट में देरी की जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता कैदी के साथ लौट आया।

स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

स्थानीय जरूरतों और जन आकांक्षा के अनुरूप स्वीकृत होंगे विकास कार्य.....

- मुख्यमंत्री साय ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक जिला मुख्यालय दुर्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख विकास कार्यों, प्राधिकरण मद से निर्माणाधीन कार्यों के अनुमोदन, प्रावधानित बजट तथा नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन करना तथा भावी विकास रणनीतियों का निर्धारण करना था, ताकि विकास का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुँच सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का समय पर एवं पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए सभी स्तरों पर सतत निगरानी आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के अंतर्गत स्वीकृत सभी विकास कार्यों, सेवाओं एवं कार्यक्रमों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के हित को प्राथमिकता में रखते हुए सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक स्वीकृत निर्माण एवं विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रगति की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसे विकास कार्य जो अब तक अप्रारंभ हैं अथवा प्रगतिरत हैं, उन्हें चिन्हित करते हुए दो माह की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से प्रत्यक्ष संवाद कर कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय नेतृत्व से परामर्श लेकर अल्पकालिक योजनाओं का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तथा जन अपेक्षाओं के अनुरूप छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की त्वरित स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

ट्रैफिक सिग्नल्स में तकनीकी खराबी के चलते वाहन आपस में टकरा रहे

रायपुर/ संवाददाता

छग की राजधानी बने रायपुर को 25 वर्ष हो गये है इसके बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था का हाल पहले से भी बदतर है। व्यस्त समय में शहर के प्रमुख मार्गों यथा जीई रोड तेलीबांधा चौक, भगत सिंह चौक, अवंतिबाई लोधी बाई चौक, शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक, शारदा चौक, स्टेशन चौक, लाखेनगर चौक, गुरुनानक देव चौक सहित सभी प्रमुख मार्गों में लगे ट्रैफिक सिग्नल्स में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण राडार में बैठे अधिकारियों द्वारा टाइमर सेटिंग नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. चंद्रमणी तिवारी जागरूक नागरिक शैलेंद्र मिश्रा एवं श्रीमती रोली मिश्रा ने नये पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला से ट्रैफिक सिग्नल्स में तकनीकी खराबी ठीक करने हेतु एसएसपी रायपुर एवं चारों जोन के सीएसपी ट्रैफिक को तत्काल निर्देश देने की मांग की है। ज्ञातव्य है कि जिन क्षेत्रों में ओव्हरब्रिज का निर्माण हुआ है वहां से लगे चौकों में अचानक हरी बत्ती बीच चौक में वाहन के पहुंचने पर लाल होती है। जिसके चलते दूसरे तरफ का ट्रैफिक छूटने की वजह से विपरीत दिशा से आ रहा वाहन चालक चौक के बीचोंबीच फंस जाता है जिसके चलते आए दिन वाहन आपस टकराते है। अधिकांश तौर पर मोवा चौक, अवंतिबाई लोधी चौक, देवेंद्र नगर चौक, कुशालपुर चौक, शंकर नगर चौक एवं अन्य ओव्हरब्रिज से लगे चौकों में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती है जिसकी वजह से लोगों का आपस झगड़ा भी होता है। अधिवक्ता जेडी बाजपेयी के अनुसार टाइमर की सेटिंग नहीं होने की वजह किस सिग्नल पर यातयात कितने सेकंड रूकेगा इसका आभास आमतौर पर वाहन चालकों को नहीं होता। कभी कभी व्हीआईपी कारकेड की वजह से भी अचानक यातायात पुलिस कर्मियों को दौड़ लगाकर ट्रैफिक रोकना पड़ता है जिसके चलते यातायात जाम की स्थिति या मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है।

डायसन एयररैप, मार्शल स्पीकर्स, आईफोन 17: क्रोमा में वैलेंटाइन्स डे सेल में सब कुछ मिल रहा है भारी छूट पर!

नईदिल्ली। भारत के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर और टाटा ग्रुप के सदस्य, क्रोमा ने इस वैलेंटाइन्स डे के लिए लाया है अल्टीमेट गिफ्टिंग गाइड, जिसमें आपको मिलेंगे ?699 से शुरू होने वाले ढेरों विकल्प। प्रीमियम डिवाइस से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरतों तक, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, वियरेबल्स, ऑडियो, पर्सनल केयर और बहुत कुछ पर विशेष कीमतें, कैटेगरी डिस्काउंट और क्यूरेटेड बंडल डील्स, आपके प्रियजन के लिए सही गिफ्ट ढूँढना आसान बना देंगे।

वैलेंटाइन्स डे ऑफर्स 6 से 15 फरवरी तक सभी क्रोमा स्टोर्स पर उपलब्ध रहेंगे। ग्राहक कैशबैक और आसान ईएमआई विकल्पों सहित कई रोमांचक लाभों का आनंद ले सकते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स सेल को और भी शानदार बनाते हैं। सभी कीमतें और ऑफर्स ब्रांड, मॉडल, स्टोर, दिन, शहर और उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, और संबंधित बैंक या फाइनेंस पार्टनर की शर्तों के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक एचडीएफसी टाटा नेउ क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके चुनिंदा उत्पादों पर 10त तक की छूट पा सकते हैं। वैलेंटाइन्स डे के खास मौके पर क्रोमा लाया है 'हीरो ऑफर्स', जहाँ आपको बेस्टसेलिंग स्मार्टफोन्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त बचत मिलेगी!

आईफोन17 अब मिल रहा है सिर्फ 47,742 में। यह ऑफर पाने का तरीका:

अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करें और 23,500 तक की वैल्यू पाएं (कंडीशन और मॉडल के आधार पर)

8,000 का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस पाएं।

2,000 का फ्लैट बैंक कैशबैक पाएं।

प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध-स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल।

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में विद्युत उपभोक्ता हुए सम्मानित

बिजली ने बदली प्रदेश के विकास की दिशा और दशा -पुरंदर मिश्रा...

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने रजत महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है विद्युत ऊर्जा । उन्होंने कहा कि राज्य के विकास की दशा और दिशा बदलने में विद्युत ऊर्जा ने बड़ी भूमिका निभाई है। विद्युत आज प्रदेश की पहचान से जुड़ा विषय है। कार्यक्रम के अध्यक्ष रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि प्रदेश का हर कोना और हर घर रोशन है तो इसमें सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की बड़ी भूमिका है। गुढ़ियारी स्थित विद्युत मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पॉवर कंपनी के विभिन्न योजनाओं के सजग विदयुत उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया । इस दौरान विधायक धरसींवा अनुज शर्मा , बिरगाँव महापौर नंदलाल देवांगन , पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर, पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला, निदेशक (सीआरए) आर ए पाठक प्रमुख रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए इसे एक आम घरेलू उपभोक्ता के लिए लाभप्रद बताया। अपने निजी अनुभवों को साझा कर उन्होंने आम लोगों से भी अधिक से अधिक इस योजना का हिस्सा बनने की अपील की।

टीम प्रहरी अभियान के तहत जोन 9 में सख्त कार्रवाई मोवा अंडरब्रिज से 14 ठेले हटाए गए

रायपुर। टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन एवं नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 9 क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सघन कार्रवाई की गई ।नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़नदस्ता एवं जोन 9 नगर निवेश विभाग द्वारा यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में यह अभियान संचालित किया गया। कार्रवाई जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा के मार्गदर्शन तथा कार्यपालन अभियंता श्री शरद ध्रुव, सहायक अभियंता श्री सैय्यद जोहेब एवं उप अभियंता श्री अतुल बंसल की उपस्थिति में की गई ।जनशिकायत के आधार पर मोवा अंडरब्रिज के नीचे अवैध रूप से लगाए गए 14 ठेलों को क्रेन की सहायता से हटाया गया। इस कार्रवाई से यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया गया तथा जनहित में समस्या का त्वरित समाधान किया गया ।इसी क्रम में जोन 9 क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर, मोवा में आवासीय क्षेत्र में संचालित एक बेकरी के संबंध में प्राप्त जनशिकायत को सही पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए बेकरी को सीलबंद किया गया।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य.....

- बैंक ऋण वापसी सुनिश्चित करने हेतु पंचायत सचिवों को दी जिम्मेदारी

रायपुर। संवाददाता

जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर की अध्यक्षता में गुरूवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)बिहान) की प्रगति की गहन समीक्षा की गई ।प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष जोरसीईओ ठाकुर ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए। लंबित आवासों की शत-प्रतिशत स्वीकृति एक सप्ताह के भीतर पूर्ण की जाए। अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के सभी पुराने लंबित आवासों एवं द्वितीय किश्त प्राप्त आवासों को मार्च माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। ठाकुर ने अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करते हुए लक्ष्य की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।

राजिम कुंभ में कोसा की चमक, कोसा रेशम से सशक्त हो रहा ग्रामीण भारत

कोसा उत्पादन किसानों को दिखा नया रास्ता,होंगे खुशहाल

रायपुर/ संवाददाता

राजिम कुंभ कल्प के नवीन मेला मैदान में गरियाबंद जिले के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभाग के योजनाओं और उनके लाभ बताए जा रहे हैं। ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग द्वारा कोसा उत्पादन की जानकारी श्रद्धालुओं और मेलार्थियों को दी जा रही है। रेशम प्रभाग के कर्मचारी रामगोपाल चौहान एवं धनसाय कटरे द्वारा कोसा निर्माण एवं उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखने और समझने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि कोसा का उत्पादन वर्ष में तीन बार किया जाता है। कोसा कीटों का पालन मुख्य रूप से कहवा और साजा के पेड़ों पर किया जाता है। पहली फसल तैयार होने में 35 से 40 दिन, दूसरी फसल में 40 से 50 दिन तथा तीसरी फसल में 60 से 70 दिन का समय लगता है। तीसरी फसल में अधिक समय लगने का कारण ठंडा मौसम होता है। सरकार द्वारा कोसा को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। यदि कोसा ए ग्रेड का होता है तो उसका मूल्य प्रति नग 5 रुपये, बी ग्रेड का 4 रुपये 15 पैसे तथा सी ग्रेड का 3 रुपये निर्धारित है। गरियाबंद जिले के किरवई, कौंदकेरा, लोहरसी, रावड़ और मालगांव क्षेत्रों में लगभग 25 एकड़ भूमि में कोसा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। कोसा उत्पादन के लिए स्वस्थ डिम्ब का मूल्य 18 रुपये प्रति नग है, जिसमें से सरकार द्वारा 16 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जबकि किसान की वास्तविक लागत मात्र 2 रुपये होती है। कोसा रेशम से निर्मित साड़ियों की बाजार में कीमत वर्तमान में

3 हजार से 4 हजार रुपये तक है। कोसा उत्पादन करने वाले किसानों को लागत सहित सालाना लगभग 5 लाख रुपये तक की आय प्राप्त हो सकती है। मेले में आए श्रद्धालु और मेलार्थी इस जानकारी को उत्सुकता से सुनते हुए कोसा उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को समझते और इससे जुड़ी संभावनाओं के बारे में जानकारी लेते नजर आ रहे हैं।

राजिम कुंभ कल्प मेला के मुख्य मंच पर नगरपालिका अध्यक्ष व डीएसपी ने दी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति

राजिम कुंभ कल्प मेला के मुख्य मंच पर चौथे दिन डॉ. पी.सी. यादव के नेतृत्व में दूध मोंगरा गंडई की लोक संस्कृति की शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। चौथे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को देशभक्ति, भक्ति और लोक संस्कृति की त्रिवेणी में डुबो दिया। मुख्य मंच पर प्रारंभ में पंडवानी कलाकार विष्णु साहू परसट्टी ने किचक वध की कथा को कपालिका शैली में प्रस्तुत किया। एक हाथ में तमुरा और दूसरे हाथ के संकेतों से उन्होंने कथा को जीवंत रूप में दर्शकों तक पहुंचाया।

संपादकीय

क्या आर्थिक समीक्षा के सुझावों से कमजोर होगा 'सूचना का अधिकार' कानून?

सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून ने देश में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन के कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। यह देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी तंत्र और उसके कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी यह कानून सरकार और जनता के बीच सूचना के सेतु के रूप में काम करता है और परस्पर भरोसे का निर्माण करता है।भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और दोषियों को कानून के कठघरे में लाने की प्रक्रिया में भी इसकी महती भूमिका है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी इन विशेषताओं में अगर कमी या कटौती की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह कानून कमजोर होगा। यह मसला इसलिए चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि संसद में हाल में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रपट में आरटीआइ कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है।तर्क दिए गए हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि गोपनीय रपट और मसविदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त की जा सके। गौरतलब है कि लंबे समय से सूचना के अधिकार की मांग के मद्देनजर वर्ष 2005 इससे संबंधित कानून को लागू किया गया था। इसके तहत देश का हर नागरिक सरकारी विभाग और संस्थाओं से उनके कामकाज, योजनाओं एवं उनके प्रभाव, वित्तीय स्थिति तथा नियमों आदि की जानकारी मांग सकता है।संबंधित अधिकारी तय समय के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होते हैं। मगर समय के साथ सरकारी तंत्र की उदासीनता, लापरवाही और निहित स्वार्थों के कारण जानकारी छिपाने के प्रयासों से इस कानून की प्रभावशीलता में कमी देखी गई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में आर्थिक समीक्षा रपट में सूचना के अधिकारों का फिर से अध्ययन करने और कुछ मामलों में छूट हासिल करने की वकालत ने चिंता के स्तर को और बढ़ा दिया है।एक तरफ सरकार जब अपने कामकाज में 'पारदर्शिता लाने' और भ्रष्टाचार को लेकर 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' की नीति अपनाने पर जोर देती हो और दूसरी तरफ सूचना के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जाए, तो यह नीति और नीयत के बीच विरोधाभास पैदा करता है। मकसद कभी भी इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का जरिया बनाने का नहीं था, न ही इसका उद्देश्य बाहर बैठकर सरकार के हर छोटे-छोटे काम में दखल देना या उसे नियंत्रित करना था।यह बात सही है कि बिना कारण या सरकार के कामकाज में किसी सुनियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करने के लिए इस कानून का सहारा लेना उचित नहीं है।

शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाला 'एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट' मॉडल सरकार की उस सोच को सामने लाता है, जो कक्षा और कार्यस्थल के बीच की खाई को पाटने का दावा करती है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपये का डीबीटी बोनस और एक करोड़ इंटर्नशिप की घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लगती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को एक ओर जहां सरकार के घटक दलों द्वारा विकसित भारत का बजट और बदलते भारत की राजनीतिक-आर्थिक प्राथमिकताओं तथा सरकार की दीर्घकालिक सोच का आईना बताया गया है, वहीं विपक्ष द्वारा इसे पूरी तरह दिशाहीन बजट करार दिया गया है। वैसे निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार बजट पेश कर संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सवाल यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है या कितने नए आंकड़े पेश किए गए हैं।

आम आदमी की आकांक्षाओं पर कितना खरा है बजट?

(योगेश कुमार गोयल)

यह है कि क्या यह बजट महंगाई से जूझ रहे आम नागरिक के वर्तमान को कुछ राहत देता है और भविष्य के लिए भरोसेमंद आधार तैयार करता है? बजट के तमाम महत्वपूर्ण प्रावधानों का आकलन किया जाए तो यह बजट विकास, निवेश, बुनियादी ढ़ांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट झलक तो दिखाता है लेकिन इसके साथ ही इसमें कई ऐसे खाली स्थान भी हैं, जो आम आदमी और विशेषकर किसान, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए निराशा पैदा करते हैं। सरकार ने इस बार तात्कालिक लोकलुभावन उपायों से दूरी बनाते हुए दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया है। यह दृष्टिकोण आर्थिक रूप से समझदारी भरा हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में बजट का मूल्यांकन केवल भविष्य के सपनों से नहीं, वर्तमान की चुनौतियों से भी होता है।शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाला 'एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट' मॉडल सरकार की उस सोच को सामने लाता है, जो कक्षा और कार्यस्थल के बीच की खाई को पाटने का दावा करती है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपये का डीबीटी बोनस और एक करोड़ इंटर्नशिप की घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लगती है। यह कदम युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में सकारात्मक है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा प्रश्न क्रियान्वयन का है। क्या ये इंटर्नशिप वास्तविक कौशल और स्थायी रोजगार की ओर ले जाएंगी या फिर यह योजना सस्ते श्रम तक सीमित रह जाएगी? भारत पहले भी कई बार योजनाओं के आकर्षक नाम और बड़े लक्ष्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर कमजोर क्रियान्वयन का अनुभव कर चुका है।

'स्किल इंडिया 2.0' के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाने की योजना डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में अहम कदम है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं के लिए यह तकनीकी दुनिया में प्रवेश का द्वार खोल सकता है लेकिन प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और उद्योग-सहयोग के बिना यह पहल भी सीमित असर तक सिमट सकती है। शिक्षा बजट को लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन बढ़ती छात्र संख्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध की जरूरतों के सामने यह राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट राहत और मायूसी का मिश्रण है। आयकर दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन आयकर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में घोषणा अवश्य की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, कर व्यवस्था को जटिल छूटों के जाल से निकालकर सरल और पारदर्शी बनाना, ताकि उपभोग बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग का संचार हो। यह दृष्टिकोण आर्थिक सुस्ती के दौर में उपयोगी हो सकता है।

सरकार ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं और क्षेत्रों में कर कटौती कर राहत देने की कोशिश की है। कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं का सस्ता होना निसंदेह करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरक्षक कदम है। मोबाइल फोन, ईवी बैटरी और सौर पैनलों पर रियायतें हरित ऊर्जा और डिजिटल इंडिया को गति देने के साथ-साथ तकनीक को आम आदमी की पहुंच में लाने का प्रयास हैं। जूते, कपड़े और कुछ घरेलू उपकरणों के सस्ते होने से मध्यमवर्गीय खपत में हल्की तेजी आ सकती है लेकिन दूसरी ओर शराब, खनिज और स्क्रैप पर बढ़े शुल्क से उत्पादन लागत बढ़ने और अंततः उपभोक्ता कीमतों पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। सबसे बड़ा झटका शेयर बाजार में देखने को मिला। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर बढ़े टैक्स ने खुदरा निवेशकों की धारणा को कमजोर किया और बजट के दौरान बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे यह संदेश गया कि सरकार सट्टात्मक गतिविधियों पर सख्ती चाहती है लेकिन इसके दुष्परिणाम अल्पकाल में निवेशकों और बाजार की स्थिरता पर पड़े। यह बजट महंगाई और निवेश के मोर्चे पर एक तरह का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, एक ओर खपत बढ़ाने की कोशिश, दूसरी ओर निवेश भावना को झटका।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ?12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सरकार की विकास रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे मार्ग शामिल हैं, भारत की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास की तस्वीर बदल सकते हैं। बेहतर परिवहन से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रियल एस्टेट को नई गति मिल सकती है। टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस शहरीकरण के असंतुलन को सुधारने की दिशा में सही कदम है। हालांकि, बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में समय लगता है और तात्कालिक रूप से निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई का दबाव बढ़ा सकती है। एमएसएमई और व्यापार जगत के लिए बजट में नई संजीवनी दिखाई देती है। 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड छोटे उद्यमों को पूंजी की कमी से उबार सकता है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना महिला उद्यमिता को वास्तविक आर्थिक ताकत देने की दिशा में अहम कदम है। टेक्निकल टेक्सटाइल पर विशेष फोकस भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिला सकता है और 'मेक इन इंडिया' को व्यावहारिक आधार दे सकता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह बजट ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार कंटेंट क्रिएटर्स और क्रिएटिव इकोनॉमी को औपचारिक मान्यता दी गई है। 'रील' और 'रियल' इकोनॉमी के बीच की दीवार लगभग गिर चुकी है। डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, एनीमेशन और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को एमएसएमई जैसा दर्जा मिलने से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि बौद्धिक संपदा संरक्षण, आय की स्थिरता और नियमन जैसे सवाल भविष्य की बड़ी चुनौतियां बने रहेंगे। स्वास्थ्य और तकनीक के मोर्चे पर 'बायो-फार्मा 2.0' और सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाता है। दवा परीक्षण और अनुसंधान के लिए 1,000 टेस्टिंग साइट्स का नेटवर्क दवाओं की लागत कम कर सकता है। सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता भारत को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत बनाएगी। रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है लेकिन नई नीतिगत घोषणाओं के अभाव में बाजार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी।

इस पूरे बजट की सबसे बड़ी कमी किसानों को लेकर किसी ठोस और नई घोषणा का न होना है। कृषि क्षेत्र अभी भी महंगाई, लागत और आय की अनिश्चितता से जूझ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना समग्र विकास अधूरा रहेगा, यह सच्चाई इस बजट में अपेक्षाकृत कम झलकती है। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 संतुलित प्रयास माना जा सकता है। यह न तो लोकलुभावन है और न ही कठोर सुधारवादी। सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए दिशा स्पष्ट की है लेकिन महंगाई, रोजमर्रा का खर्च और आय की सुरक्षा जैसी आम आदमी की तात्कालिक चिंताओं पर सीधी राहत सीमित है। यह बजट आम नागरिक को तुरंत सुकून देने के बजाय धैर्य रखने की सलाह देता है। आने वाले समय में इसका मूल्यांकन इस बात से होगा कि इसके वादे

पर्यटन बनेगा अर्थव्यवस्था का नया ग्रोथ इंजन

(विनोद पाठक)

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2026-27 में पर्यटन केवल एक सेवाक्षेत्र नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को अब वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाएगा। बजट का संदेश यही है कि पर्यटन के जरिए रोजगार और विरासत के साथ विकास हो।

बजट की सबसे क्रांतिकारी घोषणाओं में से एक 'आईआईएमप्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड्स' है। देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहली बार, गाइड्स के प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को जोड़ा गया है। यह कदम पर्यटन को अनौपचारिक से पेशेवर क्षेत्र में बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे विदेशी पर्यटकों को विश्वस्तरीय सेवा मिलेगी और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बजट में देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे सारनाथ, हस्तिनापुर को वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। उत्तर-पूर्व में बौद्ध सर्किट और हिमाचल-कश्मीर में नई हाइकिंग ट्रेल्स का विकास न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा, अपितु इन क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। भारत के सभी ऐतिहासिक स्थलों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को घर बैठे ही उन स्थलों की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

बजट में पर्यटन के आधुनिक स्वरूप को प्राथमिकता दी गई है। भारत में सीप्लेन के निर्माण और उनके संचालन के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है, जिससे तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्रों में पर्यटन सुलभ होगा। डार्क स्काई पार्क्स की स्थापना के माध्यम से खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए नए द्वार खुलेंगे। साथ ही, विदेश यात्रा के पैकेजों पर लगने वाले टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी के समान है। इससे न केवल विदेश जाना सस्ता होगा, बल्कि देश के भीतर ट्रैवल ऑपरेटर्स का कारोबार भी बढ़ेगा। 5 नए मेडिकल हब्स की स्थापना भारत को ग्लोबल हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी, जिससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा आने की उम्मीद है।

देसी पर्यटकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित गाइड्स और डिजिटल जानकारी के कारण अब भारत घूमना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और किफायती होगा। साथ ही, विदेशी पर्यटकों के लिए ई-वीजा प्रक्रियाओं में सरलीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली सुविधाओं के कारण भारत उनके बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। बजट 2026-27 पर्यटन को केवल 'घूमने-फिरने' तक सीमित नहीं रखता, अपितु इसे एक रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। बजट में भारत को वर्ष 2047 तक एक पर्यटन महाशक्ति बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं। यदि इन योजनाओं का धरातल पर सफल क्रियान्वयन होता है तो पर्यटन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ऐतिहासिक योगदान देने के लिए तैयार है। यह लेखक के निजी विचार हैं।

विकसित भारत की उड़ान- बजट 2026 के आर्थिक संकल्प

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवीन केंद्रीय बजट को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न की ठोस आधारशिला के रूप में सामने आता है। यह बजट उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह है जो बीते वर्षों में चली आर्थिक सुधारों की पटरियों पर तेज़ गति से दौड़ते हुए अब भारत को उच्च विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने का दावा करता है। तुलनात्मक, विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती बजटों की निरंतरता को बनाए रखते हुए कई नए आयाम भी जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और भविष्यगामी बनाते हैं।

(ललित गर्ग)

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र यहां नारे से आगे बढ़कर नीतिगत संरचना का रूप लेता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की दृष्टि विशेष रूप से विवेचनात्मक है। चिकित्सा अवसंरचना के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को केवल खर्च नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश मान रही है। यदि पिछले दशक के बजटों से तुलना की जाए तो स्वास्थ्य पर आवंटन और दृष्टिकोण दोनों में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह बदलाव भारत को न केवल स्वस्थ समाज की ओर ले जाने वाला है, बल्कि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को भी दीर्घकाल में मजबूती देगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट की आत्मा दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़ी शिक्षा पर बल यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य के भारत के लिए आज के युवाओं को तैयार करना चाहती है। पूर्ववर्ती बजटों में शिक्षा पर खर्च की चर्चा होती थी, लेकिन इस बजट में शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ यह बजट तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतीत होता है।

विकास की दृष्टि से यह बजट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस समावेशन' का मॉडल प्रस्तुत करता है। रेलवे कॉरिडोरों के विकास, लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, सड़क, बंदरगाह और शहरी अवसंरचना में निवेश को जिस तरह प्राथमिकता दी गई है, वह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सात रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन का माध्यम भी है। यदि इसे पिछले बजटों से जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानकर लगातार गति दे रही है।

ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट विशेष उल्लेख के योग्य है। कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, किसान कल्याण और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े प्रावधान यह संकेत देते हैं कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मंशा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल सुविधाओं, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता सुधरने की संभावना बढ़ती है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा।

नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संदर्भ में भी बजट का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से व्यापक है। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। गरीबों और वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं इस बजट को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी संतुलित बनाती हैं। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह बजट कल्याण और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, जो किसी भी दीर्घकालिक आर्थिक नीति की अनिवार्य शर्त है।

युवाओं के लिए यह बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप, नवाचार, स्किल इंडिया, रोजगार सृजन और नई तकनीकों में निवेश युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यदि इसे आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि बजट में क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक यथार्थ का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि आलोचक इसे चुनावी बजट कह सकते हैं, लेकिन विवेचनात्मक दृष्टि से यह कहना अधिक उचित होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट का जन-आकांक्षाओं से जुड़ा होना स्वाभाविक है, बशर्ते वह दीर्घकालिक विकास को बाधित न करे। इस बजट में दीर्घकालिक दृष्टि और तात्कालिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन दिखाई देता है।

समीक्षात्मक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी बजट की सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों के साथ समन्वय और पारदर्शी प्रशासन इस बजट की वास्तविक परीक्षा होंगे। फिर भी, तुलनात्मक दृष्टि से यह बजट भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रतीत होता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के विकास की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। यह वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए रास्ता तैयार करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, नारी शक्ति और युवाओं को केंद्र में रखकर यह बजट

जिला कार्यालय में हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत कार्यक्रम

परीक्षा पूर्व तनाव को कम करने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन

कोण्डागांव। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में शुक्रवार को युवोदय कोंडानार चौंप्स कार्यक्रम, यूनिसेफ एवं एग्रीकॉन समिति के सहयोग से 'हम होंगे कामयाब' अभियान के अंतर्गत परीक्षा पूर्व तनाव को कम करने हेतु एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सकारात्मक मानसिकता विकसित करना, निरंतर अभ्यास के महत्व को समझाना तथा बेहतर प्रदर्शन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से 150 से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता की, वहीं जिले के 100 से अधिक विद्यालयों के 6000 विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से सत्र से जुड़े।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वीडियो के माध्यम से प्रेरक सामग्री दिखाई गई तथा तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन एवं आत्म-प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को निरंतरता के साथ लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया समझाई और परीक्षा के दौरान उत्तर लेखन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उत्तर लिखते समय गुणवत्ता पर ध्यान देने, नियमित अभ्यास करने, सभी प्रश्नों का प्रयास करने तथा उत्तरों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के सुझाव दिए, ताकि अधिक अंक प्राप्त किए जा सकें। सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के अवरोध, घरेलू कार्यों में व्यस्त हो जाने, तैयारी होने के बावजूद परीक्षा के समय जानकारी भूल जाने तथा कम समय में रणनीति बनाने जैसी समस्याओं पर प्रश्न पूछे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट, व्यवहारिक एवं अपने अनुभवों के आधार पर दिया गया। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जिस प्रकार घोड़ा केवल सीधे आगे देखता है और आसपास की चीजों से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। सत्र के दौरान विद्यार्थियों के साथ आईवीआर हेल्पलाइन नंबर 8123922651 भी साझा किया गया, जिससे नकारात्मक विचार आने पर वे बिना किसी संकोच के संपर्क कर अपनी बात साझा कर सकें। इसके साथ ही विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से तनाव को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय तथा आत्मविश्वास को मजबूत करने के प्रभावी तरीके भी बताए गए। कार्यक्रम के दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्रा सीता सोरी ने प्रश्न किया कि पढ़ने के बाद विषय याद रहने के बावजूद परीक्षा में प्रश्न देखते ही घबराहट के कारण वे पूरा उत्तर लिख नहीं पाते या भूल जाते हैं।

वहीं आत्मानंद विद्यालय की छात्रा नीता ने परीक्षा के समय डर और घबराहट को नियंत्रित करने तथा कलेक्टर के स्वयं के अनुभवों से जुड़ी तैयारी और भय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को हम होंगे कामयाब अभियान से संबंधित सरल एवं प्रभावी सूचना-शिक्षा-संचार सामग्री का वितरण किया गया। युवोदय कोंडानार चौंप्स के स्वयंसेवकों द्वारा भी विभिन्न गतिविधियाँ करवाई गईं, जिनके माध्यम से बच्चों ने ध्यान अभ्यास एवं मनोरंजक गतिविधियों द्वारा तनाव को नियंत्रित करने के तरीके सीखे।

संयुक्त छात्रावास एकता दिवस में शामिल हुई विधायक और कलेक्टर

कोण्डागांव। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक लता उसेंडी के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को संयुक्त छात्रावास एकता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सुविधा और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर लता उसेंडी ने केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित की। साथ ही राज्य शासन द्वारा बेटियों के लिए संचालित सरस्वती सायकल योजना को बेटियों के लिए अहम् बताते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ बेटियों को पढ़ाई के प्रति रूचि और शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करना बताया , जिससे उनकी पढ़ाई बाधित न हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा बस्तर की आदिम संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर पंडुम का आयोजन किए जा रहे हैं। ताकि बस्तर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी छात्रावासों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि जिले का बालिका छात्रावास अत्यंत सुंदर है और यदि सभी छात्रावासों को इसी प्रकार स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जाए तो यह जिले की पहचान बन सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि यह आपका छात्रावास है, यह आपका बगीचा है, इसका सही उपयोग करें और इसे स्वच्छ बनाए रखें। साथ ही उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि आगामी छात्रावास दिवस के अवसर पर बस्तर की आदिवासी संस्कृति की झलक छात्र-छात्राओं के वेशभूषा में दिखाई दे।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगरपालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष नरपति पटेल, जिला पंचायत सदस्य नंदलाल राठौर, जितेंद्र सुराना, नागेश देवांगन बालसिंग बघेल, प्रदीप नाग, पूनम ठाकुर, गोविन्द रामटेके, अविनाश सोरी, रौनक पटेल एवं भोला ठाकुर सहित आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्तकृपेंद्र तिवारी छात्रावास के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।

जिला पंचायत सीईओ ने निर्माणाधीन आवासों का किया औचक निरीक्षण

कोण्डागांव। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने विकासखण्ड कोण्डागांव के ग्राम पंचायत गिरोला अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवास हितग्राही हिरामती, मेहरारिन, सावित्री, दशाय से सीधे बातचीत कर निर्माण कार्य की प्रगति एवं समस्याओं की जानकारी ली। निर्माण कार्य की गुणवत्ता व सामग्री की स्थिति की मौके पर जांच की। संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत प्रतिनिधियों व तकनीकी अमले को अपूर्ण एवं धीमी प्रगति वाले आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने व निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किए जाने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत सचिव विद्या देवांगन को कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ पत्र जारी करने एवं अप्रारंभ आवास को शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोंडागांव को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोंडागांव उत्तम कुमार महोबिया, जिला/जनपद पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव व जनप्रतिनिधिगण मुख्य तौर पर उपस्थित रहे।

अति दूरस्थ एवं पहुंच विहीन ग्राम लावा (लौहा) में कलेक्टर ने लगाई चौपाल

किरंदुल। कुआकोंडा विकासखंड के अंतिम छोर पर स्थित लावा (लौहा) के ग्रामीणों ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिले के कलेक्टर उनसे आत्मीय संवाद करके ग्राम के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की पहल करेंगें। किरन्दुल मुख्य खनन एरिया से लगभग 8 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ी एवं घनघोर वनों से घिरा हुआ लावा गांव नैसर्गिक सुंदरता घने जंगल, ऊँचे-ऊँचे पेड़,पक्षियों की मधुर आवाज और छोटे-छोटे नालों की शांत धारा के बीच अवस्थित हैं।दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पहाड़ों के बीच घुमावधार से गुजरने वाली पक्की डंडी मार्ग ही इसे किरन्दुल मुख्यालय से जोड़ती है। इसी क्रम में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव गांव लावा पहुंचे और वहां की जमीनी हकीकत का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस दौरे में विशेष बात यह रही कि कलेक्टर सीईओ सहित अन्य विभागीय अमले भी पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते में पदयात्रा करते हुए लावा गावं का सफर तय किया। इस दौरान पहाड़ियां की पकडंडी चलते समय कलेक्टर की मुलाकात अंड़री गांव से आ रहे ग्रामीण लिंगा और कमलेश से हुई। कलेक्टर ने उनसे सामान्य बातचीत करते उनके किरंदुल जाने का कारण पूछा। तो दोनों ग्रामीणों ने बताया कि वे अपने आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए किरंदुल जा रहे हैं। कलेक्टर ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूरस्थ अंचलों के लिए आधार सुधार सहित अन्य जनसेवा सुविधाएं गांव या नजदीकी पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। अगर लावा (लोहा) गांव की बसाहट की बात करे तो यहां मात्र 15 घर हैं और लगभग 60 से 70 लोग ही निवास करते हैं। सीमित आबादी होने के बावजूद भौगोलिक दुर्गमता के कारण यहां तक शासकीय सेवाओं और सुविधाओं की पहुंच चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसी क्रम में गांव पहुँचकर कलेक्टर ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और उनकी दैनिक समस्याओं व जरूरतों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने उनके समक्ष पेयजल की समस्या के साथ-साथ सड़क निर्माण की आवश्यकता, पक्के आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, विद्युत व्यवस्था जैसी आवश्यकताओं प्रमुखता से उठाया। इस पर कलेक्टर ध्रुव ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए नरेगा के माध्यम से पेयजल हेतु गांव में कुआं खोदने, सड़क निर्माण हेतु पहाड़ियों की पगडंडियों के चौड़ीकरण एवं समतलीकरण किए जाने बात कही ताकि दुपहिया एवं सायकल जैसे आवागमन के साधन आसानी से चलाये जा सके।

इसके अलावा उन्होंने गांव में ही प्री-फेब्रिकेशन मॉडल के तहत स्कूल, आगंनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक भवन बनाने तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत व्यवस्था संचालन करने को निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से उनके कृषि के अलावा कुक्कुट, मत्स्य, पशुपालन जैसे रोजगारपरक व्यवसायों को अपनाने पर हर संभव विभागीय मदद देने की बात कही।

10 साल के इंतजार के बाद बन रही सड़क में भ्रष्टाचार का डामर, अधिकारियों की चुप्पी पर उठे सवाल

भानुप्रतापपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दुर्गुकोंदल से कोदापखा तक बन रही लगभग 11 किलोमीटर की सड़क भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ग्रामीणों के लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद स्वीकृत हुई यह सड़क, ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की कमीशनखोरी के चलते अपनी गुणवत्ता खो रही है। मौके पर निर्माण कार्य की स्थिति बेहद चिंताजनक है। तकनीकी मापदंडों के अनुसार सड़क की नींव यानी डब्लू एम एम का कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है। न तो पर्याप्त पानी डाला गया और न ही वाइब्रेट हुआ। ठेकेदार द्वारा बिना डब्लूएमएम को व्यवस्थित किए सीधे इमल्शन डालकर डामरीकरण किया जा रहा है, जिससे सड़क की उम्र पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है।

फील्ड से गायब इंजीनियर, दफ्तरों में 'आराम' – शुक्रवार को जब डामरीकरण का कार्य चल रहा था, तब विभाग का एक भी जिम्मेदार अधिकारी या इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं था। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि

ठेकेदार को अधिकारियों का पूरा संरक्षण प्राप्त है – निरीक्षण न करने के एवज में अधिकारियों तक मोटी कमीशन पहुँचाई जा रही है। कार्यस्थल पर डामर की गुणवत्ता जांचने के लिए जरूरी मशीनें तक उपलब्ध नहीं हैं। सड़क निर्माण कार्य को ठेकेदार के भरोसे छोड़ कार्यालय में आराम फरामन्ते है अधिकारी।

बिना सूचना बोर्ड के गुपचुप निर्माण – हैरानी की बात यह है कि सड़क निर्माण शुरू होने के बावजूद अभी तक कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है। ग्रामीण यह तक नहीं जानते कि सड़क की लागत क्या है और इसमें किस गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग होना है। जब इस संबंध में विभाग से पूछा गया, तो इंजीनियर का तर्क था कि बोर्ड बनने दिया गया है जबकि सड़क बनकर तैयार होने की कगार पर है। लेकिन बोर्ड निर्माण अभी तक नहीं किया गया है।

आंदोलन से मिली थी सड़क, अब भ्रष्टाचार से नाराजगी – कोदापखा क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस सड़क के लिए लंबा संघर्ष किया है।

प्रशासन को जगाने के लिए कभी कीचड़ भरी सड़क पर धान की रोपाई की गई, तो कभी दुर्गुकोंदल तक पैदल यात्रा निकाली गई। 10 साल के कड़े इंतजार के बाद मिली सड़क को इस तरह बर्बाद होते देख स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है की जिस बुनियाद पर डामर बिछाया जा रहा है, वह इतनी कमजोर है कि पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने लगेगी। यह जनता के पैसे और हमारे संघर्ष का अपमान है।

विधायक ने किबई बालेंगा में 64 छात्राओं को बांटे नि:शुल्क सायकल

कोण्डागांव। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक लता उसेंडी के मुख्य आतिथ्य में ग्राम किबई बालेंगा में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर उन्होंने पर विकासखण्ड कोड़ागांव के शासकीय उच्चत्तर माध्यम विद्यालय किबई बालेंगा 64 छात्राओं को राज्य शासन द्वारा संचालित नि:शुल्क सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत सायकलों का एवं खेल सामग्री वितरण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत किबई बालेंगा गंगामुण्डा में 5 लाख 20 हजार की लागत से बनने वाली 200 मीटर सीसी सड़क का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक उसेंडी ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। सायकल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलेगी, जिससे विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी और वे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष टोमेन्द्र ठाकुर, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

नक्सल छाया से विकास की ओरः नांबी गांव में इको-टूरिज्म से आत्मनिर्भरता की नई पहल

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में अब विकास की नई तस्वीर उभरने लगी है। शासन-प्रशासन की योजनाओं और स्थानीय सहभागिता के चलते कभी नक्सल गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में अब रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह खुल रही है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के पामेड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नांबी में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के दिशा-निर्देश एवं उपनिदेशक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व श्री संदीप बलगा के मार्गदर्शन में, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व से जुड़े क्षेत्र में नक्सल योजना के तहत तीन दिवसीय सेक्टर स्पेसिफिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 फरवरी 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।कार्यक्रम की नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) रही, जबकि प्रशिक्षण Choice Consultancy Service Pvt. Ltd. द्वारा प्रदान किया गया। जिला प्रशासन एवं वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण में ग्रामीणों को होम-स्टे संचालन, अतिथि सत्कार, स्वच्छता, सुरक्षा मानक, पारंपरिक व्यंजन, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटकों से व्यवहार से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि इको-टूरिज्म के माध्यम से जंगल, वन्यजीव एवं स्थानीय संस्कृति को संरक्षित रखते हुए स्थायी रोजगार और आय के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। ग्रामीणों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे अपने गांव के भविष्य के लिए बेहद लाभकारी बताया। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से नांबी गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। साथ ही बीजापुर जिले की पहचान अब केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि इको-टूरिज्म और संरक्षण आधारित विकास मॉडल के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

साइबर अपराध के संबंध में जानकारी देना एवं साइबर अपराध से बचने का उपाय के संबंध में विस्तृत चर्चा

कोण्डागांव। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा भा0पु0से0 के द्वारा क्षेत्र में लगातार घट रहे साइबर अपराध और अपराध में उपयोग किए जा बैंक अकाउंट के संबंध में जागरूकता लाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा तथा उप पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र पुजारी के मार्गदर्शन में सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय, एवं साइबर टीम के द्वारा आज सायबर सेल कार्यालय कोंडागांव में सभी 2द्वद्धद्व प्रोवाइड, कंप्यूटर सेंटर, और चॉइस सेंटर चलाने वालों का मीटिंग आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध के संबंध में जानकारी देना एवं साइबर अपराध से बचने का उपाय के संबंध में विस्तृत चर्चा करना था। सायबर अपराधियों के तरीके - आमतौर में देखा जा रहा है कि साइबर अपराधियों के द्वारा पब्लिक 2द्वद्धद्व का उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किया जाता है एवं साइबर फ्रॉड से प्राप्त रकम को निकालने के लिए चॉइस सेंटर के बैंक खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

महतारी वंदन योजना से श्यामबती बेटियों का भविष्य कर रही सुरक्षित

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से कोण्डागांव जिले के ग्राम पंचायत बनचपई की निवासी श्यामबती कोर्राम के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। श्यामबती कोर्राम महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं। उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपये की सहायता राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। इस आर्थिक सहयोग से वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर पा रही हैं, जिससे उनके जीवन में आत्मविश्वास और संतोष की भावना बढ़ी है।श्यामबती बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा कर रही हैं। इसके साथ ही वे इस राशि से पौष्टिक आहार भी ले पा रही हैं, जिससे परिवार के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में रमेश तातेड़ 'सड़क सुरक्षा मितान' के रूप में हुए सम्मानित

केशकाल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वर्ष-2026 के अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की त्वरित सहायता में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रमेश तातेड़ को कोण्डागांव पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा मितान के रूप में सम्मानित किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा की ओर से उन्हें सम्मान-पत्र प्रदान किया गया

सम्मान पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय रहते मदद पहुंचाने, यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने तथा पुलिस प्रशासन को अपना अमूल्य सहयोग देने में रमेश तातेड़ की भूमिका सराहनीय रही है। उनके इस सामाजिक योगदान के लिए यातायात पुलिस कोण्डागांव द्वारा उन्हें सड़क सुरक्षा मितान के रूप में सम्मानित किया गया।

सर्पमित्र के रूप में भी निभा रहे अहम भूमिका– रमेश तातेड़ केवल सड़क सुरक्षा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक प्रसिद्ध सर्पमित्र भी हैं। अब तक वे सैकड़ों घरों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों से सांप पकड़ चुके हैं। खास बात यह है कि वे सांपों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं, जिससे न केवल लोगों की जान बचती है बल्कि वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार रात के समय या आपात स्थिति में भी रमेश तातेड़ बिना किसी डर के मौके पर पहुंचकर सांपों का रेस्क्यू करते हैं। उनकी तत्परता के चलते कई परिवारों ने राहत की सांस ली है।

समाज के लिए प्रेरणा बने रमेश तातेड़– सड़क सुरक्षा, मानव सेवा और वन्यजीव संरक्षण, इन तीनों क्षेत्रों में रमेश तातेड़ का योगदान समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। पुलिस प्रशासन ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि वे आगे भी इसी तरह समाजहित में कार्य करते रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार

अखंड कीर्तन-भंडारे के साथ मनाया जाएगा संतोषी माता मंदिर का चतुर्थ वार्षिकोत्सव

राजपुर। महामाया मंदिर प्रांगण स्थित संतोषी माता मंदिर का चतुर्थ वार्षिकोत्सव 11 फरवरी को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस अवसर पर अखंड कीर्तन, भंडारा तथा स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जनपद उपाध्यक्ष आकाश अशोक अग्रवाल ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सामरी विधायक उदेश्वरी पैकरा के आतिथ्य में आयोजित होंगे। वहीं लटोरी के जय मानस ग्रुप द्वारा रामायण पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है !

राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीन खेल स्पर्धा हेतु हेतु अटल विधि की महिला कबड्डी टीम धर्मशाला रवाना

बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय की कबड्डी महिला टीम, जो ईस्ट ज़ोन प्रतियोगिता में चैंपियन रही है, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हे यहतु हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के लिए प्रस्थान की ।प्रस्थान के पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति ए.डी.एन. बाजपेई ने खिलाड़ियों से भेंट कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉ. प्रमोद तिवारी जी, खेल संचालक अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, विशेष रूप से उपस्थित रहे ।टीम मैनेजर के रूप में डॉ. वसंत अंचल टीम के साथ धर्मशाला जा रहे हैं ।टीम में शामिल खिलाड़ी हैं ङ्कसंजू देवी, रोशनी, जागृति यादव, सिमरन, मनीषा, निधि, अनु, नूतन, सरोजिनी, त्रिजा ज्योति एक्का, शब्बो, चांदनी, संध्या चौहान एवं रुखसार ।उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर पर कुल 16 टीमों का चयन हुआ है, जिनमें से शीर्ष 8 टीमें आगामी सत्र में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त करेंगी ।विश्वविद्यालय परिवार को पूर्ण विश्वास है कि टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 3 में स्थान अर्जित कर छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित करेगी।

आवास हितग्राहियों के घर पहुंची जनपद टीम, आधे अधूरे आवासों पर दिया अल्टीमेटम

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशानुसार जनपद पंचायत से तखतपुर की टीम ने ग्राम पंचायत मुरु में आवास पूर्णता को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान एक 142 आवास हितग्राहियों के घर-घर पहुंचकर अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों को शीघ्र शुरू करने और पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। है, अभियान में सीईओ जनपद पंचायत पर तखतपुर सत्यव्रत तिवारी के नेतृत्व में जनपद की पूरी टीम दिनभर ग्राम मुरु में उपस्थित रही। निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए समय सीमा में आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य दिलीप ध्रुव, सरपंच ललिता पटेल सहित डीईओ, पीओ, एजीपीओ, उपअभियंता, एडीईओ, तकनीकी सहायक, उपसरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, वार्ड पंच, आवास मित्र, मेट, महिला स्व-सहायता समूह एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

निजी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई

बिलासपुर। थाना तोरवा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक युवती की निजी तस्वीरें वायरल कर बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(ए) के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति उसकी निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कर उसे परेशान कर रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की जानकारी जुटाई। जांच के दौरान लोकेशन जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र की मिली। पुलिस टीम ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने मोबाइल फोन के माध्यम से फोटो वायरल करने की बात स्वीकार की।

कलेक्टर से शिकायत के बाद भी नहीं हुई जांच

पंचायत में बिना निर्माण किए निकाल लिए गए लाखों रुपए

सरगुजा जिले के आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में पंचायत में निर्माण कार्य कराए बिना ही सरपंच सचिव के द्वारा लाखों रुपए गबन किए जाने का मामला सामने आया है ।सरपंच और ग्राम वासियों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जनपद सीईओ सहित सरगुजा के कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग की गई थी। कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो निर्माण कार्यों की जांच हुई और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल पुरा मामला लखनपुर और मैनपाट विकासखंड के सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत डांड केसरा का है। जहां के सरपंच अजीत सवता और ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत डांड केसरा मे सीसी सड़क निर्माण, ढोडी निर्माण ,नाली निर्माण, घाट कटिंग, कुआ निर्माण, संहित अन्य निर्माण कार्य पंचायत में किए बिना ही पूर्व सरपंच सचिव राम गोपाल साहू के द्वारा लाखों रुपए गबन कर लिया गया है। सरपंच अजीत सवता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मे 2025 में निर्माण कार्य किए बिना ही राशि गवन किए जाने की शिकायत जनपद के तत्कालीन को वेद प्रकाश पांडे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की गई थी। जांच नहीं होने की स्थिति में नवंबर 2025 में सरपंच और सचिव के द्वारा लाखों रुपए गबन किए जाने का मामला सामने आया है ।सरपंच और ग्राम वासियों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जनपद सीईओ सहित सरगुजा के कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग की गई थी। कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो निर्माण कार्यों की जांच हुई और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल पुरा मामला लखनपुर और मैनपाट विकासखंड के सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत डांड केसरा का है। जहां के सरपंच अजीत सवता और ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत डांड केसरा मे सीसी सड़क निर्माण, ढोडी निर्माण ,नाली निर्माण, घाट कटिंग, कुआ निर्माण, संहित अन्य निर्माण कार्य पंचायत में किए बिना ही पूर्व सरपंच सचिव राम गोपाल साहू के द्वारा लाखों रुपए गबन कर लिया गया है। सरपंच अजीत सवता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मे 2025 में निर्माण कार्य किए बिना ही राशि गवन किए जाने की शिकायत जनपद के तत्कालीन को वेद प्रकाश पांडे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की गई थी। जांच नहीं होने की स्थिति में नवंबर 2025 में सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर से शिकायत कर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी।

ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर से शिकायत कर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत करने के 3 महीने बाद भी पंचायत में किसी तरह की भी जांच नहीं हो सकी ।जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है उन्होंने शासन प्रशासन से पंचायत में सूक्ष्म जांच करते हुए सरपंच सचिव के खिलाफकार्रवाई की मांग की गई है ।पंचायत में बिना निर्माण किए निकाल लिए गए लाखों रुपए

कलेक्टर से शिकायत के बाद भी नहीं हुई जांच

सरगुजा जिले के आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में पंचायत में निर्माण कार्य कराए बिना ही सरपंच सचिव के द्वारा लाखों रुपए गबन किए जाने का मामला सामने आया है ।सरपंच और ग्राम वासियों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जनपद सीईओ सहित सरगुजा के कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग की गई थी। कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो निर्माण कार्यों की जांच हुई और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल पुरा मामला लखनपुर और मैनपाट विकासखंड के सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत डांड केसरा का है। जहां के सरपंच अजीत सवता और ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत डांड केसरा मे सीसी सड़क निर्माण, ढोडी निर्माण ,नाली निर्माण, घाट कटिंग, कुआ निर्माण, संहित अन्य निर्माण कार्य पंचायत में किए बिना ही पूर्व सरपंच सचिव राम गोपाल साहू के द्वारा लाखों रुपए गबन कर लिया गया है। सरपंच अजीत सवता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मे 2025 में निर्माण कार्य किए बिना ही राशि गवन किए जाने की शिकायत जनपद के तत्कालीन को वेद प्रकाश पांडे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की गई थी। जांच नहीं होने की स्थिति में नवंबर 2025 में सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर से शिकायत कर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी।

मनरेगा बचाओ पदयात्रा ग्राम दावा से शुरू,टी.एस. सिंहदेव रहे शामिल

उदयपुर। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ अभियान के तहत सोमवार को ग्राम दावा, थाना उदयपुर से पदयात्रा की शुरुआत की गई। पदयात्रा में भूतपूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव एवं वरिष्ठ नेता प्रेमसाय टेकाम पैदल शामिल हुए। इस दौरान टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा बनाया गया मनरेगा कानून गरीबों और मजदूरों को काम का कानूनी अधिकार देता था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने इसे कमजोर कर एक योजना में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकार समाप्त होने से ग्रामीण मजदूरों का रोजगार संकट में पड़ गया है। पदयात्रा के दौरान मनरेगा वापस दो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, टी.एस. सिंहदेव जैसा हो जैसे नारे लगते रहे। यात्रा में विकासखंड के सैकड़ों

कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं मनरेगा श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। करीब 7 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद बस स्टैंड उदयपुर में मनरेगा को बचाने मजदूरी बढ़ाने से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार विकास जिंदल को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके पश्चात स्थानीय विश्राम गृह उदयपुर में कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेमसाय टेकाम, जे.पी. श्रीवास्तव, शेखर सिंह देव, प्रमोद चौधरी, अविनाश कुमार, अनूप मेहता, जनपद अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, नीरज मिश्रा, संतोष गुप्ता, रोहित टेकाम, द्वारिका यादव, राम बिलास अग्रवाल, जगदीश जायसवाल, अमृत यादव, सूरज यादव, प्रकाश सोनी, विभा सिंह, शांति राजवाड़े, त्रिलोचन सिंह, चंदन एक्का, प्रताप सिंह, बिहारी, गोलन सिंह, योगेंद्र पैकरा, कुंजल राजवाड़े सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मनरेगा को कमजोर करने के विरोध में भैयाथान में कांग्रेस का प्रदर्शन....

ग्रामीण रोजगार संकट को लेकर उठी आवाज, योजना को मजबूत करने की मांग

सूरजपुर संवाददाता। ग्रामीण अंचल के गरीब, किसान और मजदूरों की आय का महत्वपूर्ण आधार रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को कमजोर किए जाने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भैयाथान द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती विद्यात्रि सिंह देव ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा योजना को ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी देने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह

योजना लंबे समय तक ग्रामीण परिवारों के लिए आय का मजबूत सहारा बनी रही, जिससे किसानों और मजदूरों को अपने गांव में ही काम मिलने लगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान में मनरेगा के बजट में कमी और कार्यों की सीमित उपलब्धता के कारण ग्रामीण मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम बदलने और उनके मूल उद्देश्यों को शिथिल किए जाने से आम लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। विरोध प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी अजय प्रताप सिंह, नूर आलम, लखन, शांतनु सिंह, आशीष सिंह, विनय पावले, सुनील नाविक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मनरेगा को मजबूत करने और ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की।

घुई डांडपारा में आंगनबाड़ी खोले जाने की मांग आंगनबाड़ी नहीं होने से महिला और बच्चों को होती है परेशानी

सरगुजा जिले के मैनपाट लखनपुर विकासखंड के सीमा पर स्थित ग्राम डांड केसरा घुई डांड पारा में आंगनबाड़ी नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा घुई डांड पारा में आंगनबाड़ी खोले जाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक घुई डांड पारा में लगभग दो दर्जन से अधिक परिवार निवास रथ है और प्रत्येक घरों में दो से तीन बच्चे हैं आंगनबाड़ी नहीं होने से 2 किलोमीटर दूर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आंगनबाड़ी जाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मांग की जा रही थी। मांगो उपरांत आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु सुकृति मिली जिसका निर्माण वित्त 7 वर्षों पूर्व ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु फाउंडेशन की खुदाई की गई। निर्माण एजेंसी के द्वारा कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया। लगभग 110000 रुपए राशि भी आहरण कर लिया गया। जिसे लेकर ग्रामीणों के

द्वारा शिकायत की गई थी शिकायत के बाद जांच हुई जांच में निर्माण एजेंसी पर लगभग 110000 रुपए राशि की वसूली हेतु नोटिस भी जारी किया गया था। आंगनवाड़ी भवन नहीं बनने से आज भी हुई दाल पर में समस्या जिओ की त्यों बनी हुई है ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मांग की है जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ यहां के निवासियों को मिल सके।

परियोजना अधिकारी असीम शुक्ला

इस संबंध में परियोजना अधिकारी असीम शुक्ला से बात करने पर उनके द्वारा कहा गया कि मौका जांच करने उपरांत उच्च अधिकारियों को संबंध में अवगत कराया जाएगा और ग्राम सभा का प्रस्ताव मंगवाकर आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने हेतु पहल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

प्रेमनगर में सरगुजा ओलंपिक का उत्साहपूर्ण समापन

सूरजपुर/प्रेमनगरः- प्रेमनगर विकासखंड में आयोजित सरगुजा ओलंपिक का समापन हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों एवं जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक भूलन सिंह मरावी, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य नयन सिरदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष फूलेश्वर सिरदार, जनपद उपाध्यक्ष पुनिया रजवाड़े, अतिथियों में मिथिला बंजारा, शिवनंदन मरावी, महेंद्र यादव, कंचन श्याम, परमेश्वर सिरदार, विजय सिरदार, अमीन बाई व शांति कुजूर शामिल रहे। इस पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह और खेल भावना देखने को मिली। सरगुजा ओलंपिक के अंतर्गत प्रेमनगर ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल सहित कई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ग्रामीण अंचलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक भूलन सिंह मरावी के द्वारा विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्षेत्रिय विधायक भूलन मरावी ने अपने संबोधन में कहा कि सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजनों से युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरणा मिलती है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। आगे विधायक के द्वारा ब्लॉक प्रशासन जनपद सीईओ शिवकुमार टंडन, विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रताप पैंकरा, बीपीओ रमेश कुमार जायसवाल, एबीईओ सतीश साहू, मंडल संयोजक प्रदीप सिंह, प्रभारी प्रतीक सिन्हा, खेल प्रभारी दया सिंह उइके, भोजन प्रभारी रामचरण साहू और सुनील थवाइत सहित सभी पीटीआई का सफल आयोजन व महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहना की गई। कार्यक्रम की जानकारी शा. उ. मा. विद्यालय कोटेया व्याख्याता कृष्ण कुमार ध्रुव ने देते हुए कहा प्रेमनगर विकास खंड खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में समृद्ध है। यहाँ के होनहार छात्र छात्रायें व ग्रामीण राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराकर जिले और ब्लॉक का नाम रोशन किये है। आगे अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखने और निरंतर अभ्यास करने का आह्वान किया। सरगुजा ओलंपिक का यह आयोजन प्रेमनगर ब्लॉक के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर यादगार रूप में संपन्न हुआ।

मनरेगा योजना के बदलाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में पूर्व उपमुख्यमंत्री समेत भारी संख्या में लोगों ने 10 किलोमीटर की पदयात्रा की

अंबिकापुर/मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत आज पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव के नेतृत्व में उदयपुर एवं लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के द्वारा 11 किमी से अधिक की पदयात्रा की गई। यात्रा का प्रथम चरण उदयपुर विकासखंड के ग्राम दावा से प्रारंभ होकर मनोहरपुर, विशुनपुर, मृगाडाँड़, डुमरडीह होते हुए उदयपुर में समाप्त हुई। इस दौरान उदयपुर में मनरेगा को बहाल करने और न्यूनतम मजदूरी 400 ? करने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार उदयपुर को दिया गया। दूसरे चरण में लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोसगा से ग्राम बंधा तक 3 की मी की यात्रा की गई। दोनो विकासखंड में यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्राम दावा से यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा जो इस समय सत्ता पर काबिज है मनरेगा जैसे लोककल्याणकारी योजना को समाप्त कर देश के ग्रामीण मजदूरों के रोजगार की गारंटी को समाप्त कर उन्हें कारपोरेट का बंधुआ मजदूर बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मनरेगा आम आदमी को उसके निवास क्षेत्र में काम की गारंटी देता था। केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पोषित इस योजना के फलस्वरूप ही संकट काल मे लोगों को रोजगार मिला। लेकिन रोजगार प्रदान करने वाले इस कानून को योजना के रूप में बदलकर और इसका आर्थिक भार राज्यसरकारों पर डालकर केन्द्र की मोदी सरकार एक तरह से इस महत्वाकांक्षी योजना को बरबाद करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में इन घातक बदलावों के मुख्य उद्देश्य अपने गांवों में रोजगार प्राप्त कर रहे ग्रामीणों को बेरोजगार कर उनके श्रम को कौड़ियों के

भाव अपने कारपोरेट मित्रों को सौपने का है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार वाकई में ग्रामीण मजदूरों की हितैषी है तो वो मनरेगा को पुन: बहाल करने के साथ ही साथ मजदूरी की न्यूनतम दर 400 ? करे। दोनो चरणों की इस पदयात्रा जे दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक, मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन के संभागीय प्रभारी जे पी श्रीवास्तव, सरगुजा जिले के प्रभारी डॉ प्रेमसाय सिंह, विक्रमादित्य सिंहदेव, ओमप्रकाश सिंह, अमित सिंहदेव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।

क्या मोदी सरकार देशवासियों को अमेरिका का ब्लड मिल्क पिलाएगी

यात्रा के दौरान मीडिया के द्वारा अमेरिका से हुए ट्रेड डील को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री टी एस सिंहदेव से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि मनरेगा को समाप्त कर मोदी सरकार एक ओर ग्रामीण मजदूरों को बेरोजगार कर रही है वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर देश के किसानों पर भी वज्रपात कर रही है। इस ट्रेड डील के कारण अमेरिका के किसानों की उपज विशेष तौर पर गेंहू, मक्का, दलहन और तिलहन 0 प्रतिशत टैरिफ के कारण कौड़ियों के दाम देश के बाजारों में आ जायेगा जिससे देश के किसानों को भारी घाटा होना तय है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि इस डील के कारण देश मे अमेरिका के डेयरी उत्पाद के देश मे आने की संभावना है जिसमें वहाँ का ब्लड मिल्क प्रमुख है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डेयरी फार्म अपनी गायों को कसाईखानों से निकलने वाले रक्त आदि अवशेष को चारे में मिलाकर खिलाते हैं।

वास्तु के अनुसार हो बेडरूम

बेडरूम घर का अहम हिस्सा होता है। बेडरूम का माहौल हमेशा शांत व सुकून से भरा होना बहुत जरुरी है,ताकि दिनभर की मेहनत के बाद व्यक्ति चैन से वहां आराम कर सके। बेडरूम का सही दिशा में न होना दांपत्य जीवन पर भी प्रभाव डालता है। पति-पत्नी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों के बीच आपसी तालमेल की कमी, तनाव और छोटी-छोटी बात पर झगड़ा होने का एक कारण बेडरूम में वास्तु दोष का होना भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम के भी कुछ नियम है जिन्हें अपना कर आप भी अपने संबंधों को मजबूत और मधुर बना सकते है, तो चलिए आज आपको उनके बारे में बताते है। बेडरुम घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा (नैऋत्य कोण) में होना चाहिए। बेडरूम का प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए।

कैसा होना चाहिए पलंग?

वास्तु में कहा गया है कि पलंग लकड़ी से बना होना चाहिए। इसका आकार आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। पलंग को कभी भी सीधे बीम के नीचे नहीं लगाना चाहिए। कमरे में अगर शीशा (ड्रेसिंग टेबल)लगा है तो ध्यान रखें कि सोते समय उसमें आपका अक्स दिखाई न दें, यदि उसमें प्रतिबिंब दिखता है,तो रात के समय में उसे कपड़े से ढंक दें।

किस दिशा में हो पलंग?

पलंग को दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार की तरफ होना चाहिए। पलंग को प्रवेश द्वार के ठीक सामने न लगाएं। पलंग पर पति को दाहिनी ओर और पत्नी को बायीं ओर सोना चाहिए। इससे दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा।

किस दिशा में सिर करके सोना है सही?

सोते समय सिर हमेशा पूर्व दिशा होना चाहिए। सूर्य भी पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य देव की ओर सिर करने से मानसिक और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा आप दक्षिण दिशा में भी सिर करके सो सकते हैं।

किन चीजों को बेडरूम में रखने से करें परहेज?

बेडरूम में कुछ चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि रखने से परहेज करना चाहिए।

बेसन और दूध से चमकाएं स्किन

सबसे पहले दूध 1 कप और बेसन 2 चम्मच लेकर एक बाउल में लें। फिर उसमें दूध मिला लें। अब मिश्रण में बेसन को मिलाएं। सारी चीजों को मिक्स करके पेस्ट चेहरे और बॉडी पर लगाएं। 10 मिनट के बाद त्वचा को साफ पानी से धो लें।

भारतीय घरों में सुंदरता को बढ़ाने के लिए बेसन का इस्तेमाल किया होता है। पुराने समय में जब घरों में साबुन या फिर बॉडी वॉश नहीं होते थे, तो लोग त्वचा को साफ करने के लिए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते थे। इन्हीं घरेलू नुस्खों में बेसन शामिल है। नहाने और त्वचा को चमकाने के लिए बेसन का इस्तेमाल लाभकारी साबित हो सकता है। आज भी कई लोग महंगे बॉडीवॉश या साबुन का इस्तेमाल करने की जगह बजाय बेसन ही नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज आपको इस आर्टिकल के जरिए बताते हैं कि आप बेसन का इस्तेमाल कैसे त्वचा को साफ बनाने के लिए कर सकते हैं....

सनटैनिंग होगी दूर

ज्यादा समय तक धूप में बैठे रहने के कारण त्वचा पर टैनिंग हो सकती है। धूप के कारण हाथों, पैरों, गर्दन और चेहरे की त्वचा बहुत ही जल्द प्रभावित होती है। ऐसे में त्वचा से टैनिंग दूर करने के लिए आप बेसन और दूध से नहा सकते हैं। बेसन और दूध के साथ नहाने से दाग-धब्बे दूर होंगे। टैनिंग से भी छुटकारा मिलेगा। बेसन और दूध त्वचा को टैनिंग से भी बचाता है। यदि आप सर्दियों में नहाने के लिए साबुन के जगह इस मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं,तो त्वचा बिल्कुल साफ रहेगी और टैनिंग भी नहीं होगी।

डेड स्किन सेल्स होंगे दूर

सर्दियों में त्वचा पर डेड स्किन सेल्स जमा होने लगते हैं,जिसके कारण त्वचा पर ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स जमा हो जाते हैं। ऐसे में आप नहाने के लिए बेसन और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन और दूध, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है। आप गर्मियों में चेहरे को साफ करने के लिए बेसन और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ड्राई स्किन से मिलेगा छुटकारा

हवाएं चलने के कारण स्किन ड्राई होने लगती है। ऐसे में अक्सर महिलाएं मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा नहाने के लिए महंगे साबुन या फिर बॉडीवाश का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में ड्राईनेस की दूर करने के लिए आप बेसन और दूध से बना पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है और त्वचा का रुखापन कम करता है। इससे आपको बेजान स्किन से भी छुटकारा मिलता है। वहीं दूध आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है।

फोड़े-फुंसियां होगी दूर

गलत खान-पान या फिर लंबे समय तक धूप में रहने के कारण वजह से त्वचा पर फोड़े-फुंसियां और मुंहासे होने लगते हैं। ऐसे में आप इनसे बचने के लिए बेसन और दूध के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन सीबम के उत्पादन को कम करके मुंहासों को निकालने से रोकता है। वहीं इसका इस्तेमाल करने से त्वचा के संक्रमण से भी बचाव होता है। बेसन त्वचा के मुंहासों को भी शांत करने में मदद करता है। वहीं दूध भी फोड़े-फुंसियों को मिटाने में मदद करता है।

गले की खराश से राहत पाने के टिप्स

मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। सर्दी कम हो गई है, दोपहर के वक्त तेज धूप भी निकल रही है, लेकिन फिर बीच में तेज सर्द हवाएं भी चल रही हैं। इसके चलते वायरल इंफक्शन हो सकता है और गले में खराश - खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि आप घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें। इससे गले की खराश से आपको चुटकियों में राहत मिल जाएगी।

शहद - शहद में एंटी- माइक्रोबियल और एंटी- इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं,जो गले की खराश, दर्द और खांसी को दूर करने में मदद करते हैं। शहद के सेवन से इम्यूनिटा भी बूस्ट होती है, जो इंफेक्शन से लड़ने में भी मददगार है। इसके लिए आप एक चम्मच शहद को काली मिर्च पाउडर के साथ मिला लें। दिन में कम से कम 2 बार इसका सेवन करें, आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा।

अदरक - खराश - खांसी से राहत दिलाने में अदरक बहुत असरदार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी- इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। ये सर्दी- जुकाम और खांसी की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। गले में खराश और दर्द से राहत पाने के लिए एक गिलास पानी गर्म कर लें। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर उबाल लें। फिर इसे छाने लें और इसमें शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार पीएं।

रात को पैर धोने के फायदे

बाहर से घर आने के बाद लोग अक्सर मुंह और हाथ धोना तो याद रखते हैं,लेकिन बात जब पैरों की आती है तो उसे भूल जाते हैं। पैरों को ना धोने की आदत बड़ी आसानी से आपको बीमार बना सकती है। वैसे ज्यादातर लोगों को मानना है कि पैरों में जब मोजे पहन रखे हैं, तो धोने की क्या जरूरत? लेकिन पैर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया का घर होते हैं। इन्हें धोने की लापरवाही ना केवल आपके बिस्तर को गंदा और जर्म्स से भर देती है बल्कि इसका सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट का कहना है कि रात को सोने से पहले पैरों को जरूर धोना चाहिए। इसके कई सारे फायदे होते हैं।

☛ रात को सोने से पहले पैरों को धोना बेहद जरूरी होता है। दिनभर पैर मोजे और जूते में होते है। जिससे काफी सारा पसीना होता है और जर्म्स पनपने लगते हैं। खासतौर पर जब हम अलग-अलग जगहों पर जाते हैं।

☛ पैरों में अगर सही समय पर धोया ना जाए तो इससे बैक्टीरिया पनपते हैं और अंगूठे के आसपास खुजली और नमी पैदा होने लगती है। जिससे स्किन में दिक्कत होती है और कई बार स्किन उधड़ने लगती है। जिसे एथलीट्स फुट भी कहते हैं। ऐसे में रात को सोने से पहले पैर धोना बेहद जरूरी होता है। जिससे कि इंफेक्शन ना फैले।

☛ हाइजीन मेंटेन करने के लिए पैरों को धोना जरूरी है। ये ना केवल फंगल और बैक्टीरिया इंफेक्शन बल्कि दूसरी तरीकों के इंफेक्शन के लिए भी जरूरी होता है।

☛ पैरों में अगर कट लगा हुआ है,तो फुंसी-दाना है तो इसके बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाने का डर रहता है। जिससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे में पैरों को धोना बेहद जरूरी है।

☛ इसके अलावा रात को पैरों को धोने से ना केवल पैरों की बदबू दूर होती है,बल्कि अच्छी नींद आने में भी मदद मिलती है। गर्म पानी में पैरों को डुबोकर धोने से मसल्स रिलैक्स होती है और ज्वाइंट्स में राहत मिलती है।

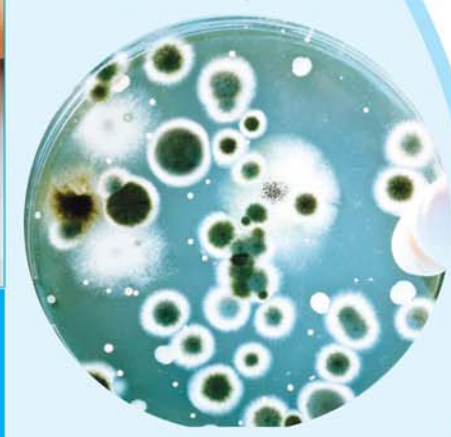

☛ डायबिटीज के मरीजों में इंफेक्शन फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। रात को सोने से पहले उन्हें पैरों को विशेषतौर पर धोना चाहिए।

☛ पैरों की मदद से डायबिटीज के मरीजों में इंफेक्शन फैलने का खतरा रहता है। लगातार चलने से पैरों में घाव होने का डर रहता है जो कि जल्दी ठीक नहीं होता है। ऐसे में पैरों के घाव की साफ-सफाई जरूरी है। पैरों के ऊतकों के खराब होने के चांस ना हो।

बचपन से ही सिखाना शुरु कर दें ये हैबिट्स

बच्चों की सुनें बात :- जब पेरेंट्स बच्चे की बात नहीं सुनते तो वह उनसे नाराज होने लगते हैं। ऐसे में आप बच्चे जब भी आपसे बात करें या आपको कुछ बताएं तो उनकी पूरी बात ध्यान से सुनें। उनकी ओर देखकर बात करें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात समझते हैं इससे वह भविष्य में अपनी बातें आपके साथ शेयर करने लगेंगे।

मोटिवेट जरुर करें :- बच्चे जब भी आपकी बात मानकर कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं या फिर कुछ अच्छा करके दिखाते हैं,तो आप उनकी तारीफ करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

साफ बात करें :- बच्चों के साथ आप जब भी बात करें, तो भाषा सिंपल ही रखें। उन्हें कई नामों से न बुलाएं। उनके साथ बात करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल भी न करें। यदि आप उनके साथ बदतमीजी से बात करेंगे,तो वह भी ऐसे ही बात करने लगेंगे। इसलिए हमेशा उनके साथ अच्छे से ही बात करें।

खुद बने रॉल मॉडल :- बच्चे हमेशा दूसरों के देखकर ही चीजें सीखते हैं। ऐसे में उनके सामने दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जिसकी आप उनसे उम्मीद रखते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में शेयरिंग की आदत आए,तो आप उनके सामने खुद भी चीजें शेयर करें।

हर बात में बच्चों को न टोकें :- बच्चे कोई भी गलती करते हैं,तो उन्हें सबके सामने न टोकें। जब आप उन्हें सबके सामने टोकेंगे,तो वह बेइज्जती महसूस करेंगे। ऐसे में बच्चों को समझाने के लिए हमेशा प्यार भरे शब्दों और उदाहरणों का इस्तेमाल ही करें।

सुबह उठते ही छींके आने की वजह जानें

वैसे तो छींक आना बहुत आम बात है पर अगर ये लगातार आए तो समस्या हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह उठते ही छींके शुरु हो जाती है और फिर कुछ समय बाद खुद से बंद हो जाती है। छींक आना नाक में हुई किसी प्रतिक्रिया का रिएक्शन होता है। रात के समय जब हम सोते है तो बहुत सी एलर्जी वाली चीजें नाक में चली जाती है। हवा में रहने वाली धूल के कण, बेडशीट और कवर के फाइबर, फंगल, बैक्टीरिया, छोटे कीड़े। रात के वक्त जब ये नाक में जाते हैं,तो सूजन आ जाती है और जब हम सुबह उठते हैं तो इन सारे कणों को नाक से बाहर करने के लिए छींके आना शुरू हो जाती हैं। वहीं कई बार हम सुबह उठते ही परागकणों के संपर्क में आते हैं जिससे भी छींके आनी शुरु हो जाती है। छींक की मदद से नाक बॉडी में साफ करती है। इसके अलावा ये भी होते हैं कारण...

तापमान का बदलना

वहीं सुबह के वक्त छींक आने का कारण शरीर के तापमान का बदलना भी हो सकता है। हम कमरे में गर्म और अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं। ऐसे में जब हम कमरे के बाहर निकलते हैं,तो शरीर को ठंडा लगता है और छींक आना शुरू हो जाती है।

कुछ लोगों को सुबह के समय चमकदार रोशनी या धूप की रोशनी के संपर्क में आने से भी छींक आनी शुरू हो जाती है।

ये घरेलू उपाय आएंगे काम

अगर आप तापमान बदलने से छींके आती हैं,तो हल्का खाना खाने की आदत डालें और डाइट में सेंधा नमक लें। 10-12 तुलसी के पत्ते में 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा कसा हुआ अदरक और 1/2 स्पून वाइन रूट पाउडर में 1 कप पानी डालकर उबाल लें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। अब इस पानी को छान लें और सुबह- शाम इसे गुनगुना पीएं।

आंवले का सेवन भी एलर्जी में फायदेमंद है। इसके लुए 1 चम्मच और थोड़ा आंवला पाउडर मिक्स करके 2 बार सेवन करें। वहीं आप आंवला- पुदीना के पत्तों से चाय भी बनाकर पी सकते हैं। इससे आराम मिलेगा। इसके अलावा भाप लेने से भी इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलती है।

दांत के दर्द के घरेलू नुस्खे

आजकल दांतों के कीड़ा लगना बहुत आम बात हो गई है। इसे मेडिकल भाषा में कैविटी कहते हैं। ज्यादा मीठा खाना, ठीक से दांतों की सफाई न करना इसका कारण होता है। दरअसल, खाने- पीने की चीजों से दांतों में प्लेक जम जाता है, इससे बैक्टीरिया बनता है, जो दांतों की सतह पर और मसूड़ों के साथ चिपक जाता है। बैक्टीरिया एसिड पैदा करते हैं, जो कैविटी का कारण बन सकते हैं। आमतौर पर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन्स नामक बैक्टीरिया को इसका मुख्य कारण माना जाता है। दांतों में कीड़ा लगने के पहले चरण के दौरान दांतों से मिनरल्स कम होने लगते हैं, जो सफेद धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यह तब होता है दांतों के इनेमल को नुकसान होता है। एक बार जब यह समस्या बढ़ जाती है, तो दांतों में असहनीय दर्द रहता है और कुछ खाया- पीया भी नहीं जाता है। ऐसे में मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहीं आप ये असरदार घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं...

नमक पानी से कुल्ले

नमक का पानी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। सूजन को कम करने और दर्द को कम करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार गर्म नमक के पानी से अपना मुंह धोएं।

ऑयल पुलिंग

ऑयल पुलिंग एक आयुर्वेदिक उपचार है जिसमें 15-20 मिनट तक अपने मुंह में तेल डालना शामिल है। यह आपके मुंह से हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, ओरल हेल्थ को बढ़ावा देता है और कैविटी को रोकता है।

लौंग का तेल

लौंग का तेल एक प्राकृतिक एनाल्जेसिक है जो कैविटी से जुड़े दर्द को कम करने में मददगार है। रुई के गोले पर थोड़ी मात्रा में लौंग का तेल डालें और इसे सीधे प्रभावित दांत पर लगाएं। दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस प्रक्रिया को दिन में कई बार दोहराएं।

ग्रीन टी

ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो ओरल हेल्थ को बढ़ावा देने और कैविटी को रोकने में मदद कर सकती है। सूजन को कम करने और कैविटीज को रोकने के लिए हर दिन एक कप ग्रीन टी पिएं।

हल्दी

हल्दी एक प्राकृतिक एंटी- इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो सूजन को कम करने और कैविटी से जुड़े दर्द को कम करने में मददगार है। इसका पेस्ट बनाने के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर में आधा चम्मच नमक और सरसों का तेल मिलाएं। इस पेस्ट को प्रभावित दांत पर लगाएं दें।

खाली पेट लहसुन खाना फायदेमंद

सुबह खाली पेट अक्सर लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। खासकर गैस और कुछ छोटी बीमारियों में अक्सर लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। आज हम इसके पीछे के कारण के बारे में बताएंगे। सुबह खाली पेट लहसुन खाने के फायदे होते हैं। आज हम आपको बताएंगे लहसुन खाने का सही तरीका-

क्यों दी जाती है खाली पेट लहसुन खाने की सलाह?

खाली पेट लहसुन खाने से हड्डियों और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से यौगिक एलिसिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने और खून को पतला करने वाली गुण पाया जाता है। खाली पेट खाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। खाली पेट लहसुन खाने से कई बीमारियों का बचाव होता है। लहसुन कई सारी एंटीबायोटिक से भरपूर होता है। अगर आप खाली पेट लहसुन खाते हैं,तो यह शरीर के लिए अधिक प्रभावी होता है। बैक्टीरिया जैसे ही एक्टिव होता है,तो लहसुन के इस्तेमाल से वह कंट्रोल में मर जाते हैं।

सुबह खाली पेट लहसुन खाने के फायदे

सुबह खाली पेट लहसुन खाने से पाचन तंत्र को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इससे पेट में पाई जाने वाली खतरनाक बैक्टीरिया मर जाती है।

इसमें पाई जाने वाली -एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द को कम कर देते हैं। लहसुन डिटॉक्सीफायर होता है। लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के कारण जोड़ों में दर्द अक्सर रहता है। लहसुन खाने से यह समस्या बढ़ सकती है। लहसुन में डिटॉक्सीफायर होता है जो कि शरीर को डिटॉक्स करता है और कई बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है।

ब्लड बैंक दुर्ग में हर वर्ष आयोजित होता है विशाल रक्तदान शिविर

बिटिया तनिशी के 14 वां जन्मदिन पर 202 यूनिट रक्तदान कर यादगार बनाया

दुर्ग। एक पिता का अपनी बेटी को लेकर प्यार ऐसा कि हर साल बिटिया परी के जन्मदिवस को यादगार बनाने और सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिता के द्वारा रक्तदान शिविर लगवाया जाता है। सिकलिंग, थैलेसिमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की नियमित आवश्यकता एवं ईलाज के दौरान रक्त की कमी होने से रक्त का अभाव न हो इसी उद्देश्य से सेवाभावी श्री तृपेश शर्मा की इकलौती पुत्री तृपेश शर्मा ''परी'' के 14वां जन्मदिवस 25 जनवरी 2026 को दुर्ग जिला ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित विशेष रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का रक्तदान करने ब्लड बैंक पर बैच व टुकड़ो-टुकड़ो में रक्तदान होता रहा तृपेश शर्मा के परिवार जनों ने भी रक्तदान किया। मित्रगण, व्यपारी वर्ग, विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को भी रक्तदान के लिये प्रेरत कर रक्तदान करवाया। रक्तदान शिविर में रूंगटा डेटल कॉलेज, पुलिस लाईन, रक्षित निरीक्षक केन्द्र, परिश्रमी सामाजिक समिति दिशा, छ.ग. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दुर्ग, चेम्बर ऑफ कार्मस, श्री जलाराम रिसायकलस दुर्ग, सेव इंडियन फैमली, नव दृष्टि फाउंडेशन, दुर्ग-भिलाई मोबाईल एशोसिएशन एवं दुर्ग भिलाई के रक्तदाताओं ने रक्तदान कर कुल 202 यूनिट रक्तदान किया। तृपेश शर्मा अपनी पुत्री ''परी'' के जन्मदिवस 25 जनवरी 2026 को रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे है विगत वर्ष 2021 को 110 यूनिट, वर्ष 2022 को 101 यूनिट, वर्ष 2023 को 147 यूनिट, वर्ष 2024 को 213 यूनिट, वर्ष 2025 को 202 यूनिट एवं वर्ष 2026 को 202 यूनिट रक्तदान किया गया शिविर में 269 लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीयन करवाया जिसमें 67 अनफिट पाये गये। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का हीमोग्लोबिन व ब्लड ग्रुपिंग की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी संग्रहित किये गये रक्तयूनिट ब्लड ग्रुप के अनुसार 202 रक्त यूनिट दान किया गया। शिविर में 15 रक्तदाताओं ने अपने जीवन का प्रथम रक्तदान 02 जोड़े पति-पत्नी, 02 जोड़े पिता-पुत्र ने रक्तदान किया। आयोजित शिविर में जिला आयुर्वेद अधिकारी दुर्ग डॉ. दिनेश चंद्रवशी ने स्वयं अपना रक्तदान किया। उमेश कुमार भागवतकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति रक्तदान को अपना कर्तव्य एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें रक्तदान के दौरान ब्लड बैंक में जमा की गई रक्त यूनिट मरीजों के जान बचाने के काम आयेगी। उनकी दुवायें सभी रक्तदाताओं और तनीषी नई उर्जा और ताकत देती रहेगी। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, श्याम शर्मा, सुरेन्द्र कौशिक, इंद्रजीत सिंह, डॉ. मनोज दानी , डॉ. आशीषन कुमार मिंज , डॉ. जय प्रकाश मेश्राम नोडल अधिकारी ब्लड बैंक जिला दुर्ग , राजेश यादव पूर्व सभापति नगर निगम, रोशन सिंह एवं समस्त ब्लड बैंक कर्मचारी, प्रमोद वाघ, , जीवन लाल ताम्रकार, सहितअन्य लोगों ने, रक्तदाताओं को उत्साहित कर प्रमाण पत्र वितरित किये एवं पुत्री तनीषी को जन्मदिवस पर दीर्घायू की कामना से शुभ-आशीष दिये।

11 एमएलडी फिल्टर प्लांट में चल रहे संधारण कार्य का जल विभाग प्रभारी लीना दिनेश देवांगन ने किया अवलोकन

गर्मी पूर्व सुचारु पेयजल व्यवस्था हेतु कवायद

दुर्ग। आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पानी की सुचारू सप्लाई व्यवस्था के लिए नगर निगम के जल कार्य विभाग द्वारा महापौर अलका बाघमार के निर्देश पर शहर में पेयजल व्यवस्था में होने वाले खामियों को दूर करने निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें एक तरफ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर छोटे बड़े लीकेज कार्य निरंतर जारी हैं तो वहीं बस स्टैंड के सामने जल गृह विभाग में स्थापित शहर की सबसे पुराने 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट में संधारण कार्य प्रगति पर है वर्तमान में ईस प्लांट में सुचारु रूप से शुद्ध पानी सप्लाई करने तकनीकी कार्यो कराया जा रहा है जिसका जल कार्य विभाग प्रभारी लीना दिनेश देवांगन ने अपने विभागीय समिति के सदस्यों के साथ अवलोकन कर अधिकारियों को शीघ्र कर सप्लाई व्यवस्था नार्मल करने के निर्देश दिए ईस दौरान समिति के सदस्य एवं पार्षद कमल देवांगन गुलाब वर्मा जल विभाग अभियंता विनोद मांझी जल कार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय की 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट दुर्ग शहर के सबसे पुरानी व पहला प्लाट है जहां से अविस्तरित दुर्ग शहर में पानी सप्लाई होता था। किंतु आबादी के विस्तार के बाद अब इस प्लांट से केवल शहर के मध्य कुछ वार्ड में ही पानी सप्लाई की जाती है जो शिक्षक नगर,जल गृह कार्यलय स्थित नई पुरानी टंकियों के माध्यम से तकिया पारा,तमेर पारा संतरा बाड़ी पोलसाय पारा केलाबाड़ी जैसे क्षेत्रों में पानी सप्लाई की जाती है किंतु अभी कुछ दिनों से संधारण कार्य के चलते उपरोक्त टंकियों में वैकल्पिक रूप से 11 एमएलडी प्लांट के बजाय रायपुर नाका स्थित बड़े प्लांट से पानी भरकर सप्लाई किया जा रहा है लेकिन शीघ्र ही ईस प्लांट के सभी तकनीकी कार्यो को पूर्ण कर गर्मी से पूर्व सही ढंग से सप्लाई व्यवस्था किया जाएगा जिसके पश्चात गर्मी में संबंधित सप्लाई वार्ड में काफी हद तक पेयजल आपूर्ति नियंत्रित होगा।

ग्राम मटिया,फरहदा स्कूलों के विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन, शिक्षा सुविधाओं को मिलेगा नया विस्तार

बलौदा बाजार । ग्राम पंचायत मटिया में शासकीय प्राथमिक शाला के अतिरिक्त भवन निर्माण की घोषणा के तहत गुरुवार को विधिवत भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं ग्राम पंचायत फरहदा में शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में तीन लाख रुपये की लागत से टाइल्स एवं पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य का भी शुभारंभ किया गया। दोनों ही विकास कार्यों की घोषणा पूर्व में जिला पंचायत सभापति ईशान वैष्णव द्वारा की गई थी, जो आज पूजा-अर्चना के साथ औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सभापति ईशान वैष्णव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। शाला भवन के अतिरिक्त कक्ष बनने से बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा और फरहदा शाला परिसर में टाइल्स व पेवर ब्लॉक लगने से स्वच्छता एवं सुविधा में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी शिक्षा, सड़क व बुनियादी सुविधाओं पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हेमंत बघमार,जनपद सदस्य प्रतिनिधि सत्या जोगी, जनपद सदस्य वीणा वर्मा, सरपंच मटिया टीकाराम निषाद, सरपंच फरहदा महिष जांगड़े, आमाकोनी सरपंच मनीष साहू, पूर्व सरपंच रोशन वर्मा, उपसरपंच अशोक, महेश यदु, बलकरण ठाकुर, भुवन साहू, लक्ष्मण साहू, प्रेम साहू, हरीश साहू, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने विकास कार्यों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्ण होने की कामना व्यक्त की।

ग्राम पंचायत पतोरा मेंसीआईएसएफ आरटीसी भिलाई ने कैम्प लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश

मल जल प्रबंधन केन्द्र, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट व सेग्रिगेशन यार्ड का किया निरीक्षण

पाटन। ग्राम पचायत पतोरा में जिला पचांयत दुर्ग, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंव वाटरएड के सौजन्य से वर्ष 2021 से संचालित है, ग्राम पचांयत पतोरा का मल जल प्रबंधन केन्द्र भारत ग्रामीण का द्वितीय एंव छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मल जल प्रबंधन केन्द्र है ग्राम पचांयत से पास स्वंय के सेक्सन (स्लज वाहन) मशीन होने के कारण आस पास के लगभग 35 km दूर से मांग के आधार फिकल स्लज लगाया जाता है फिकल स्लज में तरल अपशिष्ट जल 80 तथा ठोस अपशिष्ट का 20 है। एफएसटीपी में अलग-अलग प्रक्रिया के माध्यम दो कार्यो के लिए उपयोग किया जा रहा है। 1. तरल अपशिष्ट जल में गार्डनिग के लिए शुद्ध किया जाता है। 2. ठोस अपशिष्ट को सोना (स्वअंश) खाद बनाया जा रहा है जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।ग्राम पंचायचत के माध्यम से पचांतय व ग्रामीण स्वसहायता समूह (स्वच्छाग्राही) के लिए आजिविका साधन बन रहा है तथा ग्राम पचांयत पतोरा ग्रे वाटर मेनेजमेंट व एफएसटीपी के निर्माण होने से ग्राम व आसपास के 35 द्यद्व के ग्रामों में मल-जल की बाहर फेकने से पर्यावरण प्रदूषण व विभिन्न प्रकार बिमारियों से बचा जा सकता है व ग्रामीण आविका का माध्यम बना हुआ है। सरपंच भुनेश्वर प्रसाद साहू प्रभारी अधिकारी रंजीत सिंग व पचांयत सचिव महेन्द्र कुमार साहू द्वारा अधिकारियों से सौजन्य मुलाकात के माध्यम से तीन बैठक किया गया।

दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, मनेंद्रगढ़ में 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम का आयोजन

मनेन्द्रगढ। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, मनेंद्रगढ़ में विद्यार्थियों के मानसिक विकास और परीक्षा तनाव को दूर करने के उद्देश्य से 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रेरणादायक पहल है, जिसमें विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े तनाव, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। कायक्रम के दौरान छात्रों ने जाना कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री के संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखने, नियमित अध्ययन करने और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की प्रेरणा मिली। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने इस पहल को छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम से विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने परीक्षा को तनावमुक्त होकर देने का संकल्प लिया। विद्यालय परिवार ने इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

आज संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जायेंगे पुरी शंकराचार्य भाटापारा स्टेशन में स्वागत हेतु पहुंचने की अपील

भाटापारा। सनातन धर्म के सार्वभौम धर्मगुरू गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आज शनिवार को दुर्ग निजामुद्दीन संपर्कक्रांति एक्सप्रेस में रायपुर से दिल्ली जाएंगे। उनके ट्रेन से दिल्ली जाने की खबर से क्षेत्र के लोगों में हर्ष और उनके शिष्यों में बहुत उत्साह है । लोगो का मानना है कि छत्तीसगढ़ का परम सौभाग्य है कि पूरी शंकराचार्य जी का आगमन छत्तीसगढ़ में होते रहता है और उनका आशीर्वाद ही है जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है । पुरी के शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रतीक मान बिन्दुओं, आदर्श एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में अपने आदि गुरू शंकराचार्य की तरह भ्रमण कर रहे हैं। वे भारत की अखण्डता, भारत की सीमाओं की रक्षा, गौरक्षा, महिला जागरण, पर्यावरण रक्षा एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संदर्भ में अपने मौलिक विचारों से जन-जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। देश के बुद्धिजीवी उनके तर्कों एवं विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ रहे हैं। पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, जो राष्ट्र को नई दिशा देने में समर्थ होगी। वे समाज को सुबुद्ध, स्वावलम्बी और सत्यसहिष्णु बनाना चाहते हैं। उन्होंने अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिन्दुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा तथा देश की सुरक्षा और अखण्डता के पावन उद्देश्य से 'पीठपरिषद्' और उसके अन्तर्गत 'आदित्य वाहिनी' एवं 'आनन्द वाहिनी' नामक संस्थाओं की स्थापना की है तथा इसके माध्यम से वे सनातन संस्कृति संरक्षणार्थ राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं।

पीठपरिसद, आदित्यवाहिनी, आनंदवाहिनी से जुड़े सदस्यों और शिष्यों ने आज शनिवार को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट को भाटापारा रेलवे स्टेशन पहुंच कर शंकराचार्य भगवान के दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन धन्य करने की अपील की है।

ग्रामीण रोजगार पर वार का आरोपः मनरेगा को लेकर बलरामपुर में कांग्रेस का जोरदार धरना

बलरामपुर। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को उसके मूल अधिकार-आधारित स्वरूप में यथावत बनाए रखने और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कथित जनविरोधी परिवर्तनों को वापस लेने की मांग को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मनरेगा भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कानून है, जिसने ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मानजनक रोजगार का कानूनी अधिकार दिया है। यह केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान में केंद्र सरकार मनरेगा के मूल अधिकार-आधारित स्वरूप में ऐसे परिवर्तन कर रही है, जिससे इस कानून की आत्मा कमजोर हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा को संवैधानिक अधिकार से हटाकर एक सीमित प्रशासनिक योजना में बदला जा रहा है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों के काम के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मजदूरी निर्धारण और भुगतान में अनिश्चितता, कार्य आवंटन में देरी, पंचायतों और ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों में कटौती, ठेकेदारी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा तथा राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसी नीतियां मनरेगा के मूल उद्देश्यों के विपरीत हैं। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, पलायन, सामाजिक असुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कमजोर होने की स्थिति बन रही है। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा ने देश के सबसे कमजोर वर्ग को न केवल रोजगार की गारंटी दी, बल्कि ग्रामीण भारत में सामाजिक न्याय, समानता और गरिमा की भावना को भी सुदृढ़ किया है। कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण भारत के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए मांग की कि मनरेगा को उसके मूल अधिकार-आधारित स्वरूप में बनाए रखा जाए, पंचायतों और ग्राम सभाओं को पूर्व की भांति योजना निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी के पूर्ण अधिकार दिए जाएं तथा वर्तमान महंगाई को देखते हुए मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की जाए।

शिवरतन शर्मा ने 59 छात्राओं को किया साइकिल वितरण

भाटापारा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण ग्राम कोदवा में 59 छात्राओं को शिवरतन शर्मा ने साइकिल वितरण किया। सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जलवन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई । इस दौरान शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत भाटापारा विकासखण्ड में ग्राम कोदवा के छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया है। सभी छात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं। बेटियां है तो कल है , बेटियां पढ़ेगी विकास गढ़ेगी ।सभी बच्चें बेहतर ढंग से पढ़ाई करें और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें । हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सोच है कि शिक्षा,स्वास्थ्य, पेयजल एवं सभी क्षेत्रों में प्रदेश का समग्र विकास करना। शिवरतन शर्मा ने कहा यही समय होता है अपने लक्ष्य निर्धारित कर रुचि रख विषय को लेकर पढ़ाई करें जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा को और बेहतर रूप से करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियों को स्कूल आने में परेशानी ना हो जिसके लिए सरस्वती साईकिल योजना के तहत बेटियों को साईकिल वितरण किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए अच्छा अवसर देना हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार के मंशा के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसर होते हुए प्रदेश में बेहतर शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। इस दौरान उपस्थितजनों को संबोधित कर शिवरतन शर्मा ने डबल इंजन भाजपा सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। शिवरतन शर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी में किये वादों को पूरा करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, वहीं कल्याणकारी योजनाओं से जनता के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज हर क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात जनता को मिल रही है इससे क्षेत्र के विकास के साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है।

बकाया करों को लेकर निगम प्रशासन की सख्ती, नोटिस भी जारी कर रहे

नए बस स्टैंड की दुकानों का प्रीमियम बकाया, 7 जगहों पर निगम ने जड़ा ताला

राजनांदगांव। वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, इसे लेकर अब नगर निगम अपने बकायदारों पर सख्ती बरतता नजर आ रहा है। इसे लेकर सम्पत्तिकर, जलकर, समेकितकर के बडे बकायादारों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। हाईटेक बस स्टैण्ड जेल रोड की दुकानों का प्रीमियम जमा नहीं करने पर 7 दुकानों में ताला जड़ने की कार्रवाई की गई। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली के लिये निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, राजस्व विभाग की प्रतिदिन मानिटरिंग कर रहे हैं और बकायादारों को नोटिस जारी कर कार्रवाईके निर्देश दे रहे है। निर्देश के अनुक्रम में राजस्व अधिकारी राजेश तिवारी के नेतृत्व में निगम का अमला बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर बकाया करों का भुगतान नहीं करने की स्थिति में कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। हाईटेक बस स्टैण्ड जेल रोड के दुकानदारों में दुकान क्रं. 1 आर्बाटिति मनीष कुमार बाफना के द्वारा प्रीमियम राशि 5 लाख 14 हजार जमा की गयी व 6 लाख का अगामी तिथि का चेक दिया गया। साथ ही जिन दुकानों की प्रीमियम राशि जमा नही करने पर दुकान क्रं. जी-2 आर्बाटिति भावेश अग्रवाल बकाया प्रीमियम 11 लाख 38 हजार 7 सौ 57 रूपये, दुकान क्रं. जी-3 आर्बाटिति प्रकाश राठौर बकाया प्रीमियम 13 लाख 39 हजार 2 सौ 6 रूपये, दुकान क्रं. जी-7 आर्बाटिति मीना राठौर बकाया प्रीमियम 13 लाख 39 हजार 2 सौ 6 रूपये, दुकान क्रं. जी-8 आर्बाटिति दादा ब्रदर्स बकाया प्रीमियम 13 लाख 40 हजार 2 सौ 6 रूपये, दुकान क्रं. जी-9 आर्बाटिति भावेश अग्रवाल बकाया प्रीमियम 11 लाख 40 हजार 7 सौ 57 रूपये एवं दुकान क्रं. जी-10 आर्बाटिति दादा ब्रदर्स बकाया प्रीमियम 13 लाख 47 हजार 2 सौ 6 रूपये की प्रीमियम राशि जमा नही करने पर उक्त 7 दुकानो में ताला जडने की कार्यवाही की गई।

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव : ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रगति बेमिसाल

25 वर्षों में 74 हजार से बढ़कर 8.5 लाख हुए कृषक उपभोक्ता: गजेन्द्र यादव

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), दुर्ग क्षेत्र द्वारा शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय (साइंस कॉलेज) दुर्ग परिसर स्थित राधाकृष्ण सभागार में एक भव्य क्षेत्रीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद इन 25 वर्षों में यदि छत्तीसगढ़ ने किसी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति की है, तो वह ऊर्जा का क्षेत्र है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य गठन के समय हमारे पास मात्र 74,000 कृषक उपभोक्ता थे, जो आज बढ़कर 8.5 लाख हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ कृषि और ऊर्जा के समन्वय से कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यादव ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के योगदान को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को स्वतंत्र पहचान दिलाई। उन्होंने गंगरेल (रविशंकर जलाशय) बांध पर बिजली उत्पादन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण जो काम ढाई साल में होना था, वह रिकॉर्ड 18 महीने से भी कम समय में पूरा हुआ। मंत्री यादव ने वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर प्लांट और विद्युत ट्रांसफार्मर के नए प्लांट लगने जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर जोर देते हुए कहा कि हमें अब ऊर्जा के नए विकल्पों की ओर बढ़ना होगा ताकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल से मुक्ति मिल सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने ऊर्जा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। विशिष्ट अतिथी के रुप में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग सरस्वती बंजारे ने अपने उद्बोधन में लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com